RNI : CTHIN/25/A1911

हिन्दी दैनिक

# लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-01 ● अंक- 132 ● भिलाई, गुरुवार 27 नवम्बर 2025 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

ट्रक ने वाहन को मारी पीछे से टक्कर

## सड़क हादसा में सेना के दो जवान समेत पांच की मौत

जांजगीर-चांपा/ संवाददाता

जांजगीर चांपा जिले के सुकली एनएच 49 पर एक ट्रक और स्कॉर्पियो वाहन में जोरदार भिड़ंत हुई है। जिसमें भारतीय सेना के दो जवान सहित पांच लोगों की मौत हुई है और लोग गंभीर रूप से घायल हुए है। जिन्हें बिलासपुर रेफर किया गया है। सभी मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिए हैं। घटना के बाद ट्रक चालक फरार है, उसकी तलाश जारी है। वाहन को पुलिस ने जब्त किया है। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी अनुसार, देवांगन समाज में शादी होने पर सभी बलौदा ब्लॉक के पंतोरा बरात में गए थे। वहां से रात को लौट रहे थे, इस बीच स्कॉर्पियो में आठ लोग सवार थे। वहीं, बिलासपुर की तरफ से तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था, तभी दोनों के बीच जोरदार भिड़ंत हुई थी। घटना रात करीबन 12.30 से एक बजे की बीच की है। हादसे में स्कॉर्पियो के बैठे चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति ने बिलासपुर जाने से पहले रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं, 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें बिलासपुर सिम्स अस्पताल भर्ती कराया गया है। तीनों की स्थित स्थिर बताई जा रही है। मृतकों में दो इंडियन आर्मी के जवान थे। जिसमें राजेंद्र कश्यप और पोमेशवर जलतारे शामिल हैं। जिसमें राजेंद्र कश्यप जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पोस्टेड थे। उनकी 18 नवंबर को ही रोगदा गांव में शादी हुई थी। दो महीने



की छुट्टी में गांव आए हुए थे। वहीं, पोमेशवर जलतारे की पोस्टिंग सिक्किमी में थी, उनकी,शादी को पांच साल हो चुके हैं और उनकी तीन साल का बच्चा भी है। वह 12 नवंबर को एक माह की छुट्टी में आये हुए थे। एसपी विजय कुमार पाण्डेय ने कहा कि ट्रक मालिक से बात हो चुकी है। वाहन को जब्त किया गया है, ट्रक चालक मौके से फरार है, उसको तलाश किया जा रहा है। मृतकों का नाम विश्वनाथ देवागन पिता सुखरु देवागन (उम्र 43) राजेंद्र कश्यप पिता कोमल कश्यप (उम्र 27) पोमेश्वर जलतारे पिता पुरुषोत्तम जलतारे (उम्र 33) भूपेंद्र साहू पिता रेशम साहू (उम्र 40) कमलनयन साहू पिता रामचरण साहू (उम्र 22) घायलों का नाम सत्य नारायण साहू (35) संतोष साहू (30) दीपक केवट (25)। इस भीषण दुर्घटना और ड्राइवर की गिरफ्तारी न होने से गुस्साए नवागढ़ के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये घटना नवागढ़ में राछाभाटा चौक के पास हुई। मांग की जा रही है कि फरार ट्रक ड्राइवर की तत्काल गिरफ्तारी हो, मृतकों के परिजनों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक सड़क से नीचे उतरकर खेत के पास स्थित झाड़ियों में जा घुसा था।

### सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल.........

घटना की सूचना मिलने के बाद डायल 112 और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची.तब तक एक और युवक की गंभीर चोट लगने के कारण मौत हो चुकी थी.वहीं 3 घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया,जहां से उन्हें सिम्स अस्पताल बिलासपुर रेफर किया गया. घटना रात साढ़े 12 से 1 बजे के बीच हुई है. मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करके परिजनों को बुधवार सुबह सौंपा गया है.घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का जायजा लिया.

## संक्षिप्त समाचार

### 100 ग्राम गांजे के लिए 5 साल चला केस

**रांची।** झारखंड की राजधानी रांची में न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया और एक छोटे से अपराध को लेकर चला लंबा मुकदमा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। महज 100 ग्राम गांजा बरामदगी का एक केस रांची की अदालत में पूरे पांच साल तक चलता रहा। आखिरकार एनडीपीएसकी विशेष अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने पान दुकानदार को दोषी तो करार दिया, लेकिन सजा के तौर पर उसे वापस जेल नहीं भेजा। कोर्ट ने आरोपी द्वारा पहले ही बिताई गई 30 दिन की न्यायिक हिरासत को ही उसकी सजा मानते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है। यह पूरा मामला दिसंबर 2020 का है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नगड़ी थाना क्षेत्र के कटहल मोड़ चौक स्थित एक पान की दुकान में गांजा और अन्य नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं।

### भाभी के पास बैठे भाई को देख आपा खो बैठा पति, कुल्हाड़ी से काटकर ले ली जान

**बांदा।** उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पैलानी थाना क्षेत्र के धरिखेड़ा गांव में अवैध संबंधों के शक ने एक परिवार को उजाड़ कर रख दिया। यहां एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर अपने ही चचेरे भाई की नृशंस हत्या कर दी। 11 नवंबर को हुई इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पत्नी की पिटाई के बाद भाई पर किया हमला ग्रामीणों और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, मृतक का अपने चचेरे भाई शिवनारायण उर्फ कलुवा के घर अक्सर आना-जाना था। वह अपनी भाभी (आरोपी की पत्नी) से बातचीत करता था, जो शिवनारायण को नागवार गुजरता था। धीरे-धीरे शिवनारायण के मन में यह शक गहरा गया कि उसकी पत्नी और चचेरे भाई के बीच अवैध संबंध हैं। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन आरोपी ने दोनों को एक साथ देख लिया था, जिसके बाद वह गुस्से से आगबबूला हो गया।

### सारण में 48 घंटे में शिक्षक हत्याकांड का खुलासा, दो हथियार सप्लायर गिरफ्तार

**पटना।** पहलेजा थाना (सारण) के खरीका गाँव में हुई शिक्षक की हत्या का मामला पुलिस ने महज 48 घंटे में सुलझा दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सारण के मार्गदर्शन में अपर पुलिस अधीक्षक, सोनपुर की अगुवाई में गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने आसूचना संकलन कर सोनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भरपुरा दियारा में छापेमारी की। इस कार्रवाई में दो आर्म्स सप्लायर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान राजीव रंजन कुमार यादव (पिता स्व0 सचिन्द्र प्रसाद यादव, भरपुरा दियारा, थाना सोनपुर, जिला सारण) और रितेश कुमार (पिता सिपाही राय, भरपुरा ब्रह्मस्थान, थाना सोनपुर, जिला सारण) के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया।

बुलडोजर,सियासी दबाव पर भी दिए जवाब

## न्यायिक सक्रियता से दहशत गलत-गवई...

**नई दिल्ली।** सेवानिवृत्ति न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने आज एक इंटरव्यू में कई अहम सवालों पर बेबाकी से बात की। उन्होंने कहा, न्यायिक सक्रियता न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलनी चाहिए। अंतत:, हमारा संविधान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के संतुलन और अलग-अलग कार्यक्षेत्र पर यकीन रखता है। न्यायिक एक्टिविज्म पर अपनी राय स्पष्ट करने के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ने ये भी साफ किया, 'कई मौकों पर, नागरिक अपनी सामाजिक-आर्थिक बाधाओं के कारण, अपनी शिकायतों के निवारण



और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्थिति में नहीं होते। ऐसी स्थिति में, अगर किसी व्यक्ति को न्यायपालिका अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देती है तो ये गलत नहीं है।

लाल आंतक से मुक्त होगा छत्तीसगढ़

## 41 नक्सलियों ने आज फिर डाले हथियार एक करोड़ 19 लाख रुपये का था इनाम

**बीजापुर।** बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापना और नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक और बड़ी सफलता मिली है। राज्य शासन की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति पूना मारगेम पुनर्वास से पुनर्जीवन के सकारात्मक परिणाम सामने आते हुए आज 41 माओवादी कैडरों ने हिंसा का मार्ग त्यागकर समाज की मुख्यधारा में वापसी की। इन पर कुल एक करोड़ 19 लाख का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में 12 महिला और 29 पुरुष कैडर शामिल हैं। इन्हें साउथ सब जोनल ब्यूरो, तेलंगाना स्टेट कमेटी, धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ डिवीजन सहित डीकेएसजेडसी और पश्चिम बस्तर डिविजन से सक्रिय बताया गया है। राज्य शासन की समन्वित नीतियों शांति, संवाद, विकास और पुनर्वास ने क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए ठोस आधार तैयार किया है। सुरक्षा बलों की निरंतर सक्रियता, स्थानीय प्रशासन के प्रयासों और जनसहभागिता ने माओवादी कैडरों को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित किया है। बीते वर्षों में जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के सफल परिणाम भी देखने को मिले हैं। 01 जनवरी 2025 से अब तक 528 माओवादी गिरफ्तार, 560 समर्पित, 144 मुठभेड़ में मारे गए। वहीं 01 जनवरी 2024 से अब तक: 1031 गिरफ्तार, 790 समर्पित, 202 मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। सभी



41 कैडरों की पुनर्वास एवं पुनर्समावेशन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। राज्य शासन की नीति के तहत प्रत्येक कैडर को 50,000 की त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आगे उन्हें रोज़गार, सुरक्षा और पुनर्वास से जुड़ी सभी सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव ने कहा छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति ने माओवादियों में विश्वास जगाया है। उनके परिजन भी चाहते हैं कि वे सामान्य जीवन जिएं। हम सभी माओवादियों से अपील करते हैं कि वे हिंसा का मार्ग त्यागकर निर्भय होकर मुख्यधारा में लौटें उन्होंने आगे कहा पूना मारगेम नीति माओवादियों के भविष्य को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वावलंबी बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है।

कर्नाटक सीएम कुर्सी का घमासान

## आलाकमान सुलझाएगा मामला को राहुल-सोनिया से होगी बात

नई दिल्ली/ एजेंसी

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ शीर्ष स्तर पर चर्चा के बाद इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वहाँ की जनता ही बता सकती है कि सरकार क्या कर रही है। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि हम ऐसे मुद्दों को सुलझा लेंगे। हाईकमान के लोग - राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मैं एक साथ बैठकर इस पर विचार-विमर्श करेंगे... हम आवश्यक मध्यस्थता



करेंगे। कांग्रेस सरकार के 20 नवंबर को अपने पांच साल के कार्यकाल के आधे पड़ाव पर पहुंचने के बाद राज्य में सीएम बदलने की सुगबुगाहट के बीच हाल के हफ्तों में पार्टी के भीतर सत्ता की खींचतान तेज हो गई है। ऐसा 2023 में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के बीच कथित सत्ता-साझाकरण समझौते की पृष्ठभूमि में हो रहा है। खड़गे की टिप्पणी कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के चेहरे में बदलाव की बढ़ती अटकलों के बीच आई है, जो सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच 2023 के सत्ता-साझाकरण समझौते से प्रेरित है, जिसका राजनीतिक हलकों में अक्सर उल्लेख किया गया है। इससे पहले, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि वह और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार कांग्रेस आलाकमान के फैसले को स्वीकार करेंगे। और उसके अनुसार काम करेंगे।

### मां के पास सो रहे डेढ़ साल के बेटे को खींच ले गया कुत्तों का झुंड, परिजनों के सामने ही नोचकर मार डाला

**मेरठ।** बेगमपुल चौकी के सामने रविवार की रात कुत्तों ने खानाबदोश परिवार के डेढ़ वर्षीय मासूम को नोचकर मार डाला। घटना तब हुई जब परिवार के सदस्य बच्चे के साथ डिवाइडर पर गहरी नींद सो रहे थे। उसी दौरान मां के पास सो रहे बच्चे को कुत्ते खींच ले गए। बच्चे का शव घटना से 100 मीटर दूर सड़क पर पड़ा मिला। मासूम की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। सदर थाना क्षेत्र में बेगमपुल चौकी के सामने डिवाइडर पर रहने वाले खानाबदोश परिवार के लोग शहर की गलियों में कूड़ा बीनकर जिंदगी बसर करते हैं।

दुर्लभ धातुओं पर सरकार का बड़ा कदम

## कैबिनेट से 7280 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी..

नई दिल्ली/ एजेंसी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कुल 19,919 करोड़ रुपये की चार बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसमें 7,280 करोड़ की दुर्लभ पृथ्वी स्थायी मैग्नेट निर्माण योजना शामिल है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा क्षेत्र के लिए अहम मानी जा रही है। इसके अलावा, पुणे मेट्रो विस्तार के लिए 9,858 करोड़, देवभूमि द्वारका (ओखा)-कनालस रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए 1,457 करोड़ और बदलापुर-कर्जत तीसरी और



चौथी रेलवे लाइन के लिए 1,324 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को होने वाली बैठक में दुर्लभ पृथ्वी स्थायी मैग्नेट के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए करीब 7,280 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है, जो पहले के 2,500 करोड़ रुपये के अनुमानित पैकेज से लगभग तीन गुना अधिक है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब चीन ने निर्यात नियंत्रण कड़े कर दिए हैं। चीन वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी कच्चे माल का 60-70प्रतिशत और प्रोसेसिंग का 90प्रतिशत हिस्सा नियंत्रित करता है। केंद्रीय सरकार ने दुर्लभ मृदा स्थायी चुम्बक निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह की पहली योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य सिंटर किए गए ऋश्वक्क्रू के उत्पादन के लिए एकीकृत विनिर्माण सुविधाएं विकसित करना है।

मोदी का देशवासियों को पत्र

## संविधान की शक्ति ने साधारण व्यक्ति को पीएम पद तक पहुंचाया

नई दिल्ली/ एजेंसी

भारत आज संविधान दिवस मना रहा है। इस खास दिन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों के लिए चिट्ठी लिखी। पीएम ने अपील की है कि भारत के नागरिकों को अपने सांविधानिक कर्तव्यों को निभाना चाहिए, क्योंकि यह एक मजबूत लोकतंत्र का आधार हैं। पीएम ने अपनी यात्रा का जिक्र करते हुए पत्र में संविधान की शक्ति पर बात की उन्होंने कहा कि यह संविधान की ही ताकत थी जिसकी वजह से ही गरीब परिवार से आने वाले एक साधारण व्यक्ति प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा। पीएम ने इस पत्र में आगे मतदान के अधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूल और कॉलेज संविधान दिवस को मनाते हुए उन युवाओं को सम्मानित करें जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर पहली बार मतदाता बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी के इस विचार को याद किया कि अधिकार, कर्तव्यों के पालन से उत्पन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि कर्तव्यों का पालन सामाजिक और आर्थिक प्रगति की नींव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज लिए गए निर्णय और नीतियां आने वाली पीढ़ियों के जीवन को आकार देंगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ते हुए अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारा संविधान एक ऐसा पवित्र दस्तावेज है, जो निरंतर देश के विकास का सच्चा मार्गदर्शक बना हुआ



है। ये भारत के संविधान की ही शक्ति है जिसने मुझ जैसे गरीब परिवार से निकले साधारण व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाया है। संविधान की वजह से मुझे 24 वर्षों से निरंतर सरकार के मुखिया के तौर पर काम करने का अवसर मिला है। मुझे याद है, साल 2014 में जब मैं पहली बार संसद भवन में प्रवेश कर रहा था, तो सीढ़ियों पर सिर झुकाकर मैंने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को नमन किया। साल 2019 में जब चुनाव परिणाम के बाद मैं संसद के सेंट्रल हॉल में गया था, तो सहज ही मैंने संविधान को सिर माथे लगा लिया था। मोदी ने अपनी चिट्ठी में संविधान निर्माताओं को भी याद किया। उन्होंने कहा, संविधान दिवस पर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत उन सभी महान विभूतियों का स्मरण करते हैं, जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया है। डॉक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर की भूमिका को भी हम सभी याद करते हैं, जिन्होंने असाधारण दूरदृष्टि के साथ इस प्रक्रिया का निरंतर मार्गदर्शन किया। संविधान सभा में कई प्रतिष्ठित महिला सदस्य भी थीं, जिन्होंने अपने प्रखर विचारों और दृष्टिकोण से हमारे संविधान को समृद्ध बनाया। पीएम ने अपने पुराने अनुभव का जिक्र करते हुए कहा, साल 2010 में जब संविधान के 60 वर्ष हुए थे।

### राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को सर्वोपरि रखने का किया आह्वान

प्रधानमंत्री ने देश के भविष्य के मार्ग पर चर्चा करते हुए कहा, देखते ही देखते इस सदी के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब आने वाला समय हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है। साल 2047 तक आजादी के 100 वर्ष हो जाएंगे। साल 2049 में संविधान निर्माण के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। हम आज जो नीतियां बनाएंगे, जो निर्णय लेंगे, उसका प्रभाव आने वाले वर्षों परज्आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है इसलिए हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए ही आगे बढ़ना है। हमें राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना होगा। देश ने हमें कितना कुछ दिया है। इसके लिए हम सबके मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। जब हम इस भावना से जीवन जीते हैं।

# गांवों में विकास की रफ्तार धीमी, डौंडीलोहारा ब्लॉक सरपंचो ने गांवों में व्याप्त विभिन्न समस्या व मांगो को पूर्ण करने कलेक्टर से लगाई गुहार

## बनी पानी टंकियों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए की जांच की मांग

**बालोद।** किसी भी प्रदेश के विकास की पहली नींव गांव से रखी जाती है, और गांव की तरक्की, मूलभूत सुविधाओं का विस्तार, और जनहित की योजनाओं को ज़मीन पर उतारने की सबसे अहम ज़िम्मेदारी सरपंचों के कंधों पर होती है। लेकिन सोचिए जब वही सरपंच एक-एक सुविधा के लिए, अपने ही गांव की समस्याओं को लेकर शासन-प्रशासन के दरवाज़े पर गुहार लगाने को मजबूर हों, तो ये कितनी बड़ी विडंबना है और इसे व्यवस्था की विफलता न कहा जाए तो क्या कहा जाए। दरअसल ऐसी ही तस्वीर मंगलवार को जिला सयुंक्त कार्यालय के जनदर्शन कक्ष में देखने को मिली, जब डौंडीलोहारा ब्लॉक के दर्जनों ग्राम पंचायत के सरपंच अपने गांव में हो रही पानी की कमी, अधूरे नाली निर्माण और जर्जर सड़कों सहित अन्य मूलभूत आवश्यकताओं जैसी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन की चौखट पर पहुंचे थें। सरपंचों ने गांवों की मूलभूत समस्याओं को पूर्ण करने ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर को अवगत कराया है। 15वें वित्त कि राशि एवं मुलभुत कि राशि को पंचायत खाते में डालने सहित विभिन्न समस्या व मांगो को यथाशीघ्र पूरा करने की गुहार लगाई है।

### पंचायतों में विकास की गति धीमी

उल्लेखनीय है कि सरपंचो को पदभार ग्रहण किए 8 महीने से अधिक बीत चुके है, लेकिन अभी तक सबसे अहम निधि में से एक 15वे वित्त का पैसा अभी तक पंचायतों के खाते में नही पहुंच पाया है, जो पंचायतों के विकास कार्यों की सबसे अहम कड़ी मानी जाती है। लेकिन इस निधि के सरपंचों तक नहीं पहुंचने से ग्राम पंचायतों के विकास की गति ही थम गई है। डौंडीलोहारा ब्लॉक के सरपंचों ने ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर को अवगत कराया कि गावों में पेयजल की कमी, साफसफाई, नाली, सड़क निर्माण जैसे कार्य भी नहीं हो पा रहे है। कुछ पंचायतों में नल जल योजना के तहत बनाई गई पानी टंकी का निर्माण हो चुका है, पाइप लाइन भी घरों तक बिछाई जा चुकी है। लेकिन अब तक किसी भी घर में पानी नहीं पहुंच पाया है, तो वही कई गावों में पानी टंकियां शो पीस बन गई हैं। तो वहीं पुराने कार्यो में स्वीकृत सड़क निर्माण, नाली निर्माण और सामुदायिक भवन भी पंड न होने के कारण अधूरे पड़े हुए है, जिसके कारण सरपंचों को कार्य करने में काफी दिक्क तों का सामना करना पड़ रहा है। जियो टेग हेतु आईडी देने के अलावा सरपंचों की एक प्रमुख मांग अपने वेतन को लेकर भी है, वर्तमान में सरपंचों का वेतन 4 हजार रूपये प्रतिमाह है। लेकिन डौंडीलोहारा ब्लॉक सरपंच संघ का कहना की यह वेतन काफी कम है, जो घर चलाने के लिए भी नहीं बचता है, क्योंकि पंचायतों में कार्य इतना होता है कि उन्हें काफी ज्यादा दौरा करना पड़ता है दफ्तरों के भी चक्क र काटने पड़ते है। जिससे यह वेतन उनके लिए काफी कम है, जिसके कारण उन्होंने वेतन को 10 हजार रुपए प्रतिमाह करने की मांग की है।

### बनी पानी की टंकियों में अनिमियतता, की जाए जांच

डौंडीलोहारा ब्लॉक सरपंच संघ के अध्यक्ष पुष्पलता बघेल ने बताया कि 8 महीने बीत चुके है, लेकिन ग्राम पंचायतों में 15 वे वित्त की राशि नहीं पहुंची है। परिणामस्वरूप विकास की गति रुक सी गई है। गांव के साफसफाई जैसे छोटे कार्य भी नहीं करवा पा रहे है नल जल योजना के तहत भी पानी की टंकिया बन चुकी है, जिसमें काफी अनियमितता दिखाई दे रही, जिसकी जांच की जाए, और वर्तमान सरपंच से पूर्णतः प्रमाण पत्र लिया जाए। उन्होंने बताया कि अब तक किसी भी ग्राम पंचायतों में कोई बड़े विकास के कार्य स्वीकृत नहीं हुई है और हुई भी है तो उनका कार्य भी शुरू नहीं हुआ है। जिसके कारण सभी सरपंच काफी दुखी है। सरपंच सदन में कम से कम एक कमरा सरपंचों के लिए भी आरक्षित किया जाए, ताकि दूर दूर से आने वाली महिला सरपंचों को रुकने के लिए सुविधा हो। उन्होंने मांग की हैं कि जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत को गर्मी फसल न बोने के लिए सुचना दिया जाये, क्योंकि जल स्तर निरन्तर नीचे चला जा रहा है और ग्रामीण जन गर्मी फसल बोने के लिए तैयारी प्रारम्भ कर दिये है। जिससे पेयजल कि समस्या बढ़ती जा रही है, अतः सभी ग्राम पंचायतो को आदेशित किया जाये कि दलहन, तिलहन उत्पादन करे, पर कोई भी व्यक्ति कोई भी किसान गर्मी फसल का उत्पादन न करे, जिससे जल संकट को गर्मी कि जल संकट को रोका जा सके। ग्राम पंचायत मुड़खुसरा के सरपंच ईश्वर दयाल चंद्राकर ने कहा कि ग्राम पंचायतों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जूझना पड़ रहा है। नाली निर्माण, सड़क निर्माण, सड़क की मरम्मत, पानी की टंकिया भी अधूरी बनी हुई है। कही पुराने सरपंचों के कार्य भी नहीं हो पाए है। जिसके कारण भी पंड की कमी हुई है। उन्होंने समस्याओं व मांगो को जल्द पूरा करने की मांग उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा व कलेक्टर से की हैं।

# बालोद कलेक्टर की पहल: कलेक्ट्रेट परिसर बना आकर्षण का केंद्र, फूलों की महक और हरियाली से बदल रहा माहौल

## कलेक्टर दिव्या मिश्रा बोलीं 'सकारात्मकता से ही बनते हैं बड़े काम

**बालोद।** कलेक्ट्रेट इन दिनों एक नई पहचान बना रहा है। प्रशासनिक गतिविधियों के बीच जहाँ आमतौर पर तनाव, भीड़ और परेशानियों का माहौल रहता है, वहीं बालोद कलेक्ट्रेट का मुख्य परिसर अब खूबसूरत फूलों और हरे-भरे पौधों से सजा एक शांत सुकून भरा स्थान बन गया है। प्रवेश द्वार पर स्थित फुलवारी में खिले गेंदा और अन्य रंग-बिरंगे फूल लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहें हैं। जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से प्रतिदिन सैकड़ों लोग अपनी समस्याएँ लेकर कलेक्ट्रेट पहुँचते हैं, लेकिन परिसर में प्रवेश करते ही लोगों के चेहरे पर खुशी और राहत की मुस्कान आ जाती है। कई लोग यहाँ खिले फूलों के बीच सेल्फी और तस्वीरें लेते नज़र आते हैं। यह सरल-सी पहल अब लोगों के मन में कलेक्ट्रेट के प्रति एक सकारात्मक छवि बना रही है। इतना ही नही परिसर में तमाम तरह के लगे छांवदार वृक्ष और उनकी सुरक्षा को लेकर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभी कुछ महीनों पहले किये गए वृक्षारोपण की ट्री गार्ड लगाकर सुरक्षा की जा रही है। पार्किंग की भी व्यवस्था बदल गई है। आगे गार्डन बनाने की भी तैयारी की जा रही है।

### फूल सकारात्मक ऊर्जा देते हैं: दिव्या मिश्रा

इस पहल के बारे में पायनियर से चर्चा करते हुए कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने कहा जब हम अपने आसपास हरियाली और खूबसूरत फूलों को देखते हैं, तो यह हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है। यही सकारात्मकता हमें बेहतर काम करने, लोगों की समस्याओं को संवेदनशीलता से समझने और समाधान के लिए प्रेरित करती है। बालोद की सभी उपलब्धियाँ इसी सकारात्मक सोच और सामूहिक प्रयास का परिणाम हैं। कलेक्टर दिव्या मिश्रा की यह सोच न सिर्फपरिसर की सुंदरता में झलकती है, बल्कि उनके प्रशासनिक कामकाज में भी दिखाई देती है।

### जल संरक्षण में राष्ट्रीय पहचान, सकारात्मक सोच का परिणाम

बालोद की यह सौंदर्यीकरण पहल किसी अलग-थलग प्रयास का हिस्सा नहीं है। हाल ही में जिले ने 'जल संचय, जन भागीदारी' अभियान (JSJB 1.0) में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पूर्वी ज़ोन में पहला स्थान हासिल किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलेक्टर दिव्या मिश्रा को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। अभियान के दौरान जिले में 3 लाख 88 हजार से अधिक पौधारोपण, हजारों जल संरचनाएँ, तालाबों का पुनरुद्धार और व्यापक जनसहभागिता से प्रशासन ने जल संरक्षण को एक जन-आंदोलन का रूप दिया। हरियाली को लेकर कलेक्टर का यह जुनून ही जिले की पहचान को नई ऊँचाइयों तक लेकर गया है।

### कलेक्ट्रेट परिसर: प्रशासन का चेहरा बदलने की एक पहल

कलेक्ट्रेट की फुलवारी यह संदेश देती है कि प्रशासन सिर्फ फाइलों और दफ्तरों का नाम नहीं, बल्कि सकारात्मक वातावरण और बेहतर अनुभवों का भी केंद्र हो सकता है। बालोद कलेक्टर की यह पहल बताती है कि सौंदर्यीकरण और हरियाली सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि लोगों के मनोबल और प्रशासनिक माहौल को बेहतर करने का एक सशक्त माध्यम है।

# युकां ने बिजली बिल के विरोध में भरी हुँकार नगर में वोट चोर गद्दी छोड़ का पोस्टर चस्पा

## युकां के प्रदेश प्रभारी व सहप्रभारी हुए शामिल

**डोंगरगांव नगर।** नगर में छग युवक कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अमित पठानिया, सहप्रभारी मोनिका मंडरे प्रदेश व प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा का आगमन हुआ। युकां ने नगर भ्रमण कर विभिन्न चौक चौराहों में वोट चोर गद्दी छोड़ के स्लोगन लिखे हुए पोस्टर चस्पा किये। इस दरम्यान युकांईयों ने बिजली बिल में इजाफे के विरोध में जमकर गर्जना करते हुए 2028 में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने हुंकार भरी। नगर के इंदिरा गाँधी भवन में सर्वप्रथम छग युवक कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अमित पठानिया, सहप्रभारी मोनिका मंडरे प्रदेश व प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के मार्गदर्शन में युवा कांग्रेस राजनांदगाव के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व मे जिला युवा कांग्रेस राजनांदगाव ग्रामीण की बैठक डोंगरगाँव नगर मे आहूत की गई। बैठक में वोट चोर गद्दी छोड़, बिजली चोर गद्दी छोड़ सहित महंगाई व बिजली बिलों में इजाफे के विरोध में सरकार की नाकामी को को जन जन तक पहुंचाने के लिए बैठक रखा गया। पश्चात् युवा कांग्रेस द्वारा नगर भ्रमड़ कर वोट चोर गद्दी छोड़ का पोस्टर चौक चौराहो पर चस्पा किया गया। युवा कांग्रेस के प्रभारी अमित पठानिया, सह प्रभारी मोनिका मंडरे, प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा व युवानेता निखिल द्विवेदी ने युवाओ को सम्बोधित करते हुवे संगठन को मजबूत करने पर जोर देते हुए युवा कांग्रेस के कार्यो की समीक्षा की। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष महेश सेन, विधानसभा अध्यक्ष सौरभ वैष्णव तथा युवानेता लिलेश पटेल ने एक स्वर में कहा कि युवा कांग्रेस का एक एक सिपाही अपने बूथ स्तर पर मेहनत कर रहा है उनको संगठन मे मौका दिया जायेगा। वही जो युवा पद लेकर आराम कर रहे है उन पर संगठन शिकंजा कसेगी। सभा का संचालन पार्षद प्रियंक जैन ने किया। बैठक में प्रमुख तौर पर युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अमित पठानिया, सह प्रभारी मोनिका मंडरे, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी, विधायक प्रतिनिधि टिकेश साहू, किसाननेता मदन साहू, महिला कांग्रेस अध्यक्ष संध्या साहू मंचस्थ थे। नगर भ्रमण में महेंद्र यादव, डॉ नरेंद्र साहू, राकेश साहू, श्रुति शुक्ला, शशांक खोब्रागढे, शरद वैष्णव, हरेंद्र साहू, तुषार यादव, संदीप डहरे, युगल देवांगन, गिरीश साहू, भानु साहू, कोमल मंडावी, चाणक्य गोस्वामी, डोमार मंडावी, सुधीर पटेल, अजय श्रीवास, अमित ठाकुर, अभय लोढ़ा, अब्दुल, राकेश साहू, इदरीश, सिब्बू देवागन, हेमंत देवाँगन, रुपेश, राजा वैष्णव सहित अनेक युकांई शामिल हुए।

# रियायती दर पर शक्कर वितरण की अंतिम तिथि 29 नवम्बर

**कवर्धा।** भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित राम्हेपुर कवर्धा में अंशधारी सदस्यों रियायती दर पर शक्कर वितरण किया जा रहा है। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यातिद कवर्धा के पेराई सीजन 2025-26 के संचालन को दृष्टिगत रखते हुए समस्त अंशधारी सदस्यों को रियायती दर पर शक्कर वितरण की अंतिम तिथि 29 नवंबर निर्धारित की गई है। कारखाना प्रबंधन समस्त अंशधारी सदस्यों से अपील करता है कि उक्त तिथि तक शक्कर का उठाव अनिवार्य रूप से कर लेवें। निर्धारित अवधि के बाद अंशधारी सदस्यों को रियायती दर पर शक्कर का वितरण नहीं किया जावेगा। अंशधारी सदस्यों को रियायती दर 30 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति शेयर 50 किलोग्राम शक्कर प्रदाय किया जा रहा है। अंशधारी सदस्यों को शक्कर प्राप्त करने के लिए शेयर प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, पिछले वर्ष 2024 में रियायती दर की मनी रसीद की छायाप्रति, अंशधारी सदस्य की आईडी प्रूफ के रूप में वोटर आईडीकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लाईसेन्स बैंक पास बुक इत्यादि, अंशधारी सदस्य के अधिकृत सदस्य को भेजने की स्थिति में अधिकृत करने संबंधी आवेदन एवं अधिकृत सदस्य का आधार कार्ड, रियायती दर पर 30 रू. प्रति किलो के मान से राशि जमा कर शक्कर प्राप्त करना होगा। रियायती दर पर शक्कर वितरण कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से सांय 04 बजे तक (अवकाश दिवस) को छोड़कर किया जा रहा है।

# कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने धान उपार्जन केंद्र डौंडी का आकस्मिक निरीक्षण किया

दल्लीराजहरा। कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने धान उपार्जन केंद्र डौंडी का आकस्मिक निरीक्षण किया । उन्होंने धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्था, कटे फटे बारदाना और सिलाई में अनियमितता पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने डौंडी के समिति प्रबंधक रजऊ राम ठाकुर को हटाने तथा उनके स्थान पर अन्य किसी प्रबंधक को प्रभार देने हेतु तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपने समक्ष धान से भरे बोरे की सिलाई कराई तथा तौल हुए बोरे का पुनः वजन कराया। उन्होंने धान खरीदी कार्य में बेहतर ढंग से निगरानी नहीं करने पर निगरानी समिति के सदस्यों को फटकार भी लगाई।

# सरकार ने दी शराब प्रेमियों को नई सौगात दल्ली राजहरा में शुभारंभ हुआ प्रीमियम वाइन शॉप

## सुरा प्रेमियों में उल्लास मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी

**दल्लीराजहरा।** प्रदेश की सुशासन वाली साय सरकार ने दल्ली राजहरा के शराब प्रेमियों को बड़ी सौगात दी ही। यहां के शराब प्रेमी लोगों को अब अच्छी क्वालिटी की शराब मिलने लगी है। यहां के मदिरा प्रेमी अब प्रीमियम का लुत्फउठाने लगे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन की प्रदेशव्यापी योजना के तहत प्रत्येक नगर में प्रीमियम श्रेणी की शराब दुकानों की स्थापना का कार्य निरंतर जारी है। इसी क्रम में दल्ली राजहरा में भी हाल ही में शासकीय प्रीमियम शराब दुकान का उद्घाटन किया गया। दुकान की शुरुआत के बाद नगर में उत्सुकता के साथ-साथ विभिन्न वर्गों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल रही हैं। शराब प्रेमी जहां आल्हादित हो उठे हैं, मुख्यमंत्री से कह रहे हैं- थैंक्स साय जी। वहीं आम नागरिक इस पहल को सामाजिक पतन का एक और जरिया करार दे रहे हैं। दुकान खुलने की सूचना मिलते ही मदिरा प्रेमियों के बीच उल्लास छा गया है। उनका कहना है कि प्रीमियम श्रेणी की गुणवत्तापूर्ण शराब अब स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होने से बाहर के शहरों पर निर्भरता कम होगी साथ ही शासकीय नियंत्रण में उपलब्ध उत्पादों की शुद्धता व सुरक्षा को लेकर भी वे संतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं। नगर के कई नागरिक यह उम्मीद जता रहे हैं कि प्रीमियम दुकान की शुरुआत से लंबे समय से विभिन्न वार्डों में चल रहा अवैध शराब कारोबार तथा मिलावटी मदिरा की बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगेगा। उनका मानना है कि जब शुद्ध मदिरा आसानी से उपलब्ध होगी, तो शराब के अवैध धंधों का करोबार स्वतः कम हो जाएगा। इसके अलावा पहले शासकीय दुकान तक पहुंचने में रास्ते की दुर्गम स्थिति का सामना करना पड़ता था, जिससे अब राहत मिलने की संभावना है। हालांकि कुछ मोहल्लों के निवासियों ने दुकान की स्थापना पर चिंता भी जताई है। उनका कहना है कि ऐसी दुकानों की उपलब्धता बढ़ने से सामाजिक परिवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। विरोध करने वाले लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस प्रकार के निर्णयों में स्थानीय जनमत एवं क्षेत्रीय परिस्थितियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। फिर भी नगर के अधिकांश लोगों का मानना है कि प्रीमियम दुकान शुरू होने से अवैध शराब बिक्री में कमी आएगी, जिससे न केवल राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी बल्कि सुरा प्रेमियों का मिलावटी व हानिकारक शराब के सेवन से बचाव होगा।

# बेमेतरा जिले में शीत ऋतु की तैयारियां तेज, डिप्टी कलेक्टर पिंकी मनहर नोडल अधिकारी नियुक्त

**बेमेतरा।** आगामी शीत ऋतु में संभावित शीतलहर, अत्यधिक ठंड तथा मौसम संबंधी जोखिमों से आमजन को सुरक्षित रखने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 17 नवंबर 2025 को जारी निर्देशों के अनुरूप जिले में सभी विभागों को आवश्यक सावधानियाँ अपनाने तथा जनजागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली एवं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा शीतलहर से बचाव हेतु जारी दिशानिर्देशों का जिला, जनपद, नगर पालिका, तहसील और ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि नागरिक समय रहते सावधान रहें और ठंड के प्रभाव से बच सकें।

### जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किसी भी आपात स्थिति में करें संपर्क

जिला प्रशासन ने शीतलहर से संबंधित आपदा प्रबंधन के लिए सुश्री पिंकी मनहर, डिप्टी कलेक्टर, को जिला नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। किसी भी आपात स्थिति, तापमान में अचानक गिरावट, शीतलहर के प्रभाव या राहत संबंधी जानकारी हेतु आम नागरिक उनके मोबाइल/व्हाट्सऐप नंबर 88175-94204 पर संपर्क कर सकते हैं।

### प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता—जागरूकता पर विशेष जोर

जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निम्न निर्देशों के प्रचार-प्रसार के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है अत्यधिक ठंड के दौरान घर से बाहर निकलने पर गर्म कपड़े पहनें। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएँ, बच्चे एवं बीमार लोग विशेष सावधानी बरतें। खुले में आग जलाने से परहेज़ करें, सुरक्षित तरीकों से ही गर्माहट प्राप्त करें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एसओपी का पालन सुनिश्चित करें।आश्रयहीन एवं जरूरतमंद लोगों हेतु रैन बसेरों की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। शीत ऋतु के दौरान संभावित आपदा जोखिमों को देखते हुए प्रशासन सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर राहत एवं बचाव कार्यों को तैयार रखने में जुटा है। कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि वे मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट का पालन करें और किसी भी आपात परिस्थिति में तुरंत प्रशासन से संपर्क करें।

# एस आई आर को लेकर प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी की उपस्थिति में हुई बैठक

**बेमेतरा।** बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी के राजीव भवन में छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जांगिड़ के मुख्य आतिथ्य में जिला कांग्रेस कमेटी भवन में एस आई आर को लेकर बैठक रखी गई थी।

जिसमें प्रदेश सहप्रभारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तथा बूथ लेवल एजेंट को एस आई आर को लेकर समझाया जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की बी एल ओ से समन्वय बनाकर कांग्रेस कार्यकर्ता मतदाताओं को एस आई आर गणनापत्रक भरने में सहायता प्रदान करें तथा निर्धारित समय अवधि में कार्य को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को सजग रहकर इस बात पर भी ध्यान देना है कि कहीं किसी प्रकार से प्रशासन के द्वारा अथवा भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा फर्जी मतदाताओं को जोड़ा ना जा रहा हो उनकी मैपिंग न कराई जा रही हो तथा योग्य मतदाताओं का नाम काटने की कोई साजिश ना रची जा रही हो वास्तविक मतदाता का मैपिंग हो तथा फर्जी मतदाता इस एस आई आर से मतदाता सूची से बाहर हो इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सजग रहना होगा रिसोर्स पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जिसमें उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्र में मतदाताओं के साथ मिलजुल कर उनके एस आई आर फॉर्म सही तरीके से भरे जा रहे हैं या नहीं इस पर मतदाताओं की सहायता करने एवं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किसी प्रकार से फर्जी मतदाता के नाम से मैपिंग ना किया जाए इस पर ध्यान रखने की बात कहीं इस अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारी सहित भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही।

## संक्षिप्त समाचार

### सहकारी समितियों के कर्मचारी के काम पर वापस आने से खरीदी में आई तेजी

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अब तेज हो गई है। धान छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और किसानों की जीवन रेखा है। सरकार ने 2739 धान खरीदी केन्द्रों में आवश्यक सुविधा सुनिश्चित की है। इसके चलते धान खरीदी में तेजी आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में समर्थन मूल्य पर 3100 रूपए प्रति क्विंटल दर 25 लाख किसानों से धान खरीदी की जा रही है, 15 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी होगी। 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में डिजिटल सर्वे करा लिया गया है। 2739 धान खरीदी केन्द्रों सदृढ़ व्यवस्था की गई है। किसानां को 7 दिनों भुगतान करन होगा। किसानों से एक लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जाएगी, इसके लिए मॉनिटरिंग एवं नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। मार्कफेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है, इसके लिए इंटीग्रेटेड कमाण्ड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस खरीदी में परिवहन और रियल टाईम मॉनिटरिंग संभव होगी। प्रत्येक जिले में कंट्रोल रूप स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ के लगे ओड़िशा, महाराष्ट्र एवं आंध्रप्रदेश व मध्य प्रदेश से धान की अवैध आवक हद्दती है, इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक सीमावर्ती क्षेत्रों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। इसके बावजूद धान खरीदी की अवैध आवक नहीं हो रहा है। धान खरीदी के लिए पर्याप्त साधन की व्यवस्था की गई है। करीब एक लाख गठान बारदाना खरीदी गया है। छत्तीसगढ़ में भारत शासन के खाद्य विभाग के लिए 23 लाख चावल केन्द्रीय पुल निर्धारिक किया गया है। किसानों को उचित समय भुगतान की सीमा तय की गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों को समय पर भुगतान मिले यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। धान खरीदी केन्द्रों में टोकर तोहर हाथ मोबाइल एप्प के माध्यम से सुविधा शुरू की गई है। किसान अपनी सुविधा के अनुसार तिथि समय चुनकर टोकर पास कर सकें गे। धान खरीदी के दौरान बायामैट्रिक सुविधा सुनिश्चित की गई है। राज्य में धान खरीदी के लिए करीब 40 हजार करोड़ रूपए खर्च होंगे। वहीं 10 लाख रूपए के भुगतान को भी निशिचित कि है सहकारी समितियों के हड़ताल में चले जाने के कारण यह खरीदी प्रभावित हो गई थी, अब वे वापस आ गए हैं।

### धान खरीदी व्यवस्था सुव्यवस्थित करने नवीन टोकन व्यवस्था

**रायपुर।** राज्य शासन के निर्देशानुसार धान खरीदी प्रणाली को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित तरीके से संचालित किए जाने हेतु इस वर्ष टोकन जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल तथा किसान हितैषी बनाया गया है। किसानों की सुविधा के लिए नवीन टोकन व्यवस्था लागू करते हुए निर्धारित पात्रता के आधार पर टोकन जारी किए जा रहे हैं। शासन द्वारा जारी व्यवस्था के अनुसार 2 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को अधिकतम 1 टोकन, 2 से 10 एकड़ तक के कृषकों को अधिकतम 2 टोकन तथा 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को अधिकतम 3 टोकन की पात्रता निर्धारित की गई है। किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने टोकन तुहर ऐप की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके माध्यम से कुल उपलब्ध टोकनों में से 80 प्रतिशत टोकन लघु एवं सीमांत किसानों के लिए तथा 20 प्रतिशत टोकन दीर्घ किसानों के लिए आरक्षित किए गए हैं। किसान अपनी सुविधानुसार ऐप में लॉगिन कर निर्धारित मानदंडों के अनुसार टोकन प्राप्त कर सकते हैं। किसानों द्वारा आवेदन करने की तिथि से अगले सात खरीदी दिवस तक का टोकन जारी किया जा सकता है। समितियों के माध्यम से टोकन वितरण रविवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन प्रात: 9:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक किया जा रहा है। वहीं टोकन तुहर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने की सुविधा प्रतिदिन प्रात: 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध है। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील किया है कि वे नवीन टोकन व्यवस्था का लाभ उठाते हुए अपने निर्धारित समय में ही धान लेकर खरीदी केंद्र पहुंचे।

### बैंक में बंधक मकान सौदा कर 40 लाख रूपये की ठगी,दो आरोपी गिरफ्तार

**रायपुर।** बिलासपुर के सरकंडा थानाक्षेत्र में दो लोगों के द्वारा एक व्यक्ति को बैंक में बंधक मकान को दिखाकर उसका बिक्री ईकरारनामा तैयार कर उससे 40 लाख रूपये ले लेने तथा रजिस्ट्री नही कर धोखाधड़ी करने की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बिना नामांतरण कराये बैंक में बंधक मकान को बिक्री करने का सौदा किया था। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी अजीत शुक्ला पिता जे.एल. शुक्ला उम्र 57 वर्ष निवासी सूर्या विहार सरकण्डा का दिनांक 22.11.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका परिचय दिनेश प्रताप सिंह के साथ है जिससे भेंट मुलाकात होते रहता था, परिचय होने के कारण दिनेश प्रताप सिंह ने अप्रैल 2024 में भास्कर त्रिपाठी नामक व्यक्ति से अपने निवास में मिलवाया जिसने बताया कि वह एसईसीएल कोरबा में कार्यरत् है जिसका मकान विवेकानंद नगर मोपका में है जिसे वह बिक्री करना चाहता है, जिसे देखने के बाद मैंने खरीदी करने का ईच्छा जताया तब भास्कर त्रिपाठी ने उक्त मकान को बिक्री करने के लिए मुझसे 50 रूपये के स्टाम्प पेपर में दिनांक 26.04.2024 को इकरारनामा तैयार कराया।

---

उद्योग और पर्यटन को मिलेगा बूस्ट

# छत्तीसगढ़ को मिले 6800 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव

- छत्तीसगढ़ देश का सबसे भरोसेमंद और तेज़ी से उभरता औद्योगिक गंतव्य- मुख्यमंत्री
- दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में 3,000 से ज्यादा रोजगार का खुला रास्ता

रायपुर। संवाददाता

राजधानी दिल्ली आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को अभूतपूर्व निवेश प्रस्ताव मिले। स्टील, ऊर्जा और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों ने राज्य में उद्योग स्थापित करने, क्षमता विस्तार, होटल निर्माण और वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए रुचि दिखाई। कार्यक्रम में शामिल कंपनियों ने कुल 6321.25 करोड़ के औद्योगिक निवेश और 505 करोड़ का पर्यटन निवेश का प्रस्ताव दिया है। इन परियोजनाओं से आगामी वर्षों में 3,000 से अधिक रोजगार अवसर सृजित होने की उम्मीद है। इस निवेश प्रस्ताव के साथ अब तक छत्तीसगढ़ को कुल 7.90 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। दिल्ली स्थित होटल द ललित में आज आयोजित कार्यक्रम में स्टील और टूरिज़्म सेक्टर को केंद्र में रखते हुए नए निवेश अवसरों पर फोकस किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने उद्योग जगत के प्रमुख निवेशकों, विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की एवं स्टील और टूरिज़्म सेक्टर की कई कंपनियों को निवेश प्रस्ताव पत्र सौंपे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, भारत सरकार के केमिकल और उर्वरक मंत्रालय के सचिव अमित अग्रवाल, इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पौंडरिक भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ आज देश के सबसे भरोसेमंद, स्थिर और तेज़ी से उभरते हुए औद्योगिक गंतव्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य में ऊर्जा, खनिज, सक्षम मानव संसाधन और निवेशक-हितैषी नीति का ऐसा संयोजन मौजूद है, जो किसी भी उद्योग के लिए अत्यंत उपयुक्त वातावरण तैयार करता है। उन्होंने बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत अनुमतियाँ अब पहले की तुलना में अधिक तेज़ी और पारदर्शिता के साथ जारी हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाना आज पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। राज्य में कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, टिन, लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की उपस्थिति बड़े औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र के लिए वरदान है। उन्होंने कहा कि हाल ही में आयोजित 'एनर्जी समिट' में राज्य को साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और कई परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। मुख्यमंत्री साय ने स्टील सेक्टर का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ देश का स्टील हब है, जहां भिलाई स्टील प्लांट, नगरनार स्टील प्लांट और एमएसएमई आधारित स्टील इकाइयां राज्य की औद्योगिक पहचान को मजबूती प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा भिलाई स्टील प्लांट पिछले 70 वर्षों से देश की औद्योगिक प्रगति का स्तंभ रहा है और इसकी उपस्थिति ने स्टील आधारित उद्योगों का प्राकृतिक इकोसिस्टम तैयार किया है। ग्रीन स्टील और नवीकरणीय ऊर्जा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य राज्य के लिए नए अवसर लेकर आया है और छत्तीसगढ़ इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। टूरिज़्म सेक्टर पर बात करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर आज बहुत बदल रहा है। नक्सल हिंसा में कमी आई है, सड़कें, इंटरनेट और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर अब निवेश और पर्यटन दोनों का नया केंद्र बन रहा है।

---

# माकड़ी ब्लॉक में 100 पीएम सूर्य घर का सफल इंस्टालेशन

रायपुर। संवाददाता

कोंडागांव जिले का माकड़ी ब्लॉक आज पूरे बस्तर संभाग में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया केन्द्र बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर सोलर विज़न को वास्तविक रूप देने वाली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने इस क्षेत्र में न केवल सुलभ ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित की है, बल्कि इससे ग्रामीण जीवन में बड़ा बदलाव आया है। डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर मॉकडी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 100 घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम को सफलतापूर्वक ग्रिड से सिंक्रोनाइज करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है, जो साबित करती है कि दूरस्थ और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भी सौर ऊर्जा अपनाने की जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अब तक जिले में कुल 284 घरों में सोलर पैनल लग चुका है, जिसमें 50 से अधिक इंस्टॉलेशन सिर्फ ग्राम माकड़ी में ही किए गए हैं।उक्त योजना के तहत घरों की छतों पर स्थापित सोलर पैनल से घरेलू खपत की पूर्ति में सक्षम होते हैं और बिजली की अतिरिक्त उत्पादन से आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पहल की सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र और राज्य शासन की संयुक्त सब्सिडी ने ग्रामीण परिवारों के लिए सोलर सिस्टम लगवाना बेहद आसान कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली बड़ी सब्सिडी के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य शासन भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह सब्सिडी सीधे डीबीटी के माध्यम से उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा होती है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, सरल और भरोसेमंद बन गई है।माकड़ी ब्लॉक में सौर ऊर्जा अपनाने के बाद परिवारों के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आए हैं। बिजली बिलों में भारी कमी आई है, कई घरों में मासिक बिल लगभग शून्य होने लगा है। ग्रिड-कनेक्शन होने की वजह से ग्रामीणों को दिन-रात स्थिर बिजली उपलब्ध हो रही है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।

### कांग्रेस अब अपने पतन की ओर बढ़ चुकी है नलिनीश ठोकने

**रायपुर।** भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने ने राजनांदगाँव में प्रदेश युवा कांग्रेस की अंदरूनी कलह के खुलकर सामने आने युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी की बैठक से युकां कार्यकर्ताओं की किनाराकशी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि इससे साफपता चल रहा है कि कांग्रेस का संगठनात्मक ढाँचा कितनी बुरी कदर चरमरा गया है! श्री ठोकने ने कहा कि चुनावों में लगातार हारती जा रही कांग्रेस अब अपने पतन की पराकाष्ठा की ओर बढ़ चुकी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठोकने ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक लगातार हार के बावजूद अपने संगठनात्मक ढाँचे की जरा भी फिक्र नहीं कर रहे हैं, जो कांग्रेस और उससे जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों के अपमान से जगजाहिर हो रहा है।

---

जमीन की सरकारी कीमत मार्केट रेट से ज्यादा

# कांग्रेस जनों ने किया पंजीयन कार्यालय के सामने प्रदर्शन....

- पंजीयन शुल्क को 4 प्रतिशत रखने की मांग
- जांच कराकर नया रेट लागू करना चाहिए

रायपुर। संवाददाता

राज्य शासन के द्वारा जमीन की नई रजिस्ट्री दर लागू करने के विरोध में आज कांग्रेसजनों ने जिलाधीश कार्यालय में जंगी प्रदर्शन किया। रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय द्वारा मिली जानकारी के अनुसार राज्य में आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर जमीन की नई रजिस्ट्री दरें लागू की गई है, जिसके कारण बिल्डरों एवं गरीबों में काफी रोष है। जिसके कारण यहां पर जमीन की खरीदी बिक्री प्रभावित होगी। वहीं चोर दरवाजा भी खुल जाएगा जिसके चलते यहां शासन को घाटा होगा वहीं शासन को राजस्व की क्षति होगी। उपाध्याय ने आरोप लगाया कि राज्य में डायवर्सन नहीं होने से वैसे भी गरीब लोग और किसान परेशान है। इस तरह नई रजिस्ट्री के रेट जारी होने से लोग परेशान हो जाएंगे। आज जिला पंजीयन एवं स्टाम्प कार्यालय के सामने विकास उपाध्याय सहित जिलाध्यक्ष एवं विभिन्न पदाधिकारियों ने भाग लिया। यहां पर लोगों ने सरकार के विरूद्ध जमकर नारे बाजी की है। याद रहे कि राजधानी में इस समय बड़ी संख्या में बिल्डर सक्रिय है। नए रेट के बढ़ाने से यहां पर लोग परेशान हो जाएंगे। वैसे भी रजिस्ट्री कराने के लिए काफी परेशानी लोगों को होती है। इधर बिल्डरों ने आरोप लगाया कि कई जगहों में जमीन की सरकारी कीमत मार्केट रेट से ज्यादा हो गई है।

---

# एसआईआर, पुराना रिकॉर्ड लोगो की बढ़ाई परेशानी..

- एक पता एक घर पोलिंग बूथ अलग-अलग
- राजधानी के सीमावर्ती जिलों से आए लोग ऑनलाइन देख रहे मतदाता सूची

रायपुर। संवाददाता

राजधानी में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का काम जोरो से चल रहा है, इसके तहत शहर के विभिन्न वार्डों में बीएलओ ने घर-घर जाकर एसआईआर का फार्म वितरित कर दिया है, लेकिन गलत जानकारी और पुराने रिकार्ड में लोगों की परेशान बढ़ा दी है। लोगों की समस्याए ये है कि पता जशपुर का है, लेकिन रहना रायपुर में हो रहा है, इसी तरह की शिकायत धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग जिले के लोगों की भी है, जो कि अब 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम खोजने को लेकर परेशान हैं। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी में इस समय बीएलओ तथा राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बीएलए भी फार्म भराने को लेकर सक्रिय हैं। अब बीएलओ भी इस बात को लेकर परेशान है कि मतदाता सूची क्रम नहीं है। एक मतदाता का नाम एक कॉलोनी में है तो दूसरा का पता किसी और कालोनी में दर्ज है। कई मतदाता किराए में रहते अब यहां से चले गए हैं। मठपुरैना तथा अन्य क्षेत्रों में भी यही समस्या है, जिससे सत्यापन का काम कठिन हो गया है। लोगों से अपील की गई है कि 2003 की मतदाता सूची ऑनलाईन देखें। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में चलाए जा रहे मतदाता सूचियां के विशेष गहण पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रम के तहत वर्तमान में गणना चरण का कार्य चल रहा है। इस दौरान कोई भी वैध मतदाता ना छूटे और कोई अवैध नाम शामिल न हो उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए बूथ लेवल अधिकारी द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों में भी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं और उनसे गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं।

### पहाड़-नदियों को पार कर हर मतदाता तक पहुँच रहा लोकतंत्र का संदेश....

**रायपुर।** भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने दुर्गम इलाकों में भी रफ्तार पकड़ ली है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीमें और बीएलओ सुदूर पहाड़ी अंचलों, घने जंगलों और नदी-नालों से होकर हर घर तक पहुँच रही हैं, ताकि कोई भी नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। ज्ञात हो कि जिले में वर्तमान में 92,637 मतदाता पंजीकृत हैं। वर्ष 2025 की मतदाता सूची को आधार मानकर बीएलओ लगातार घर-घर गणना पत्रक वितरित कर रहे हैं। इन पत्रकों को भरना सभी मतदाताओं के लिए अनिवार्य है। अब तक 47.02 प्रतिशत गणना पत्रक प्राप्त कर उनके डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। विशेष पुनरीक्षण के इस चरण में वर्ष 2025 के पंजीकृत मतदाताओं का मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से किया जा रहा है। मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को निर्धारित है। सूची में उसी मतदाता का नाम शामिल किया जाएगा, जिसका गणना पत्रक बीएलओ को प्राप्त हो गया हो या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किया गया हो। प्रारंभिक प्रकाशन के बाद दावे और आपत्तियाँ 8 जनवरी 2026 तक स्वीकार की जाएंगी।

---

# जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड छत्तीसगढ़ में 1816 करोड़ रुपये का निवेश करेगी

रायपुर। संवाददाता

भारत की प्रमुख सीमेंट निर्माता कंपनी जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड ने आज छत्तीसगढ़ में अपने एकीकृत विनिर्माण संचालन के बड़े विस्तार की घोषणा की। कंपनी 2.31 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) क्लिंकर क्षमता और 1.2 एमटीपीए सीमेंट ग्राइंडिंग क्षमता बढ़ाने की योजना बना रही है, जिसके लिए 1,816 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इस निवेश का एमओयू आज नई दिल्ली में आयोजित 'छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट' कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित किया गया, जहां राज्य ने प्रमुख औद्योगिक अवसर प्रस्तुत किए। जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, श्री श्रीवत्स सिंघानिया ने कहा, यह विस्तार जेके लक्ष्मी सीमेंट के अगले विकास चरण को आकार देने में महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ हमारी विनिर्माण रणनीति का मुख्य हिस्सा रहा है, और यह निवेश हमें पूर्वी और मध्य भारत में विश्वसनीय और कुशल क्षमता के साथ सेवा देने में सक्षम बनाएगा। यह हमें स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल प्रणालियों और प्रभावी कार्यान्वयन पर आधारित भविष्य-तैयार संगठन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। हमारा ध्यान राज्य से जुड़े समुदायों और बाजारों के लिए दीर्घकालिक और टिकाऊ मूल्य निर्माण पर केंद्रित है। छत्तीसगढ़ लगातार सीमेंट उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण विकास केंद्र बन रहा है। इसका कारण है राज्य में चल रहा अवसंरचना विकास, बढ़ती आवास जरूरतें और समृद्ध खनिज संसाधन। इन मजबूत क्षमताओं को देखते हुए, जेके लक्ष्मी सीमेंट ने छत्तीसगढ़ को अपनी दीर्घकालिक विस्तार योजना का मुख्य हिस्सा बनाया है। नई क्षमता जुड़ने से कंपनी पूर्वी और मध्य भारत के तेजी से बढ़ते बाजारों की मांग को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेगी। यह विस्तार आने वाले वर्षों में क्षमता को लगभग 30 एमटीपीए तक बढ़ाने के कंपनी के लक्ष्य को भी मजबूत करता है। पिछले दशक में, जेके लक्ष्मी सीमेंट ने 2015 में दुर्ग में अपना एकीकृत संयंत्र स्थापित करने के बाद से छत्तीसगढ़ के औद्योगिक परिदृश्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंपनी ने कई पहलें की हैं—1.8 एमटीपीए क्लिंकर और 2.7 एमटीपीए सीमेंट क्षमता वाले अत्याधुनिक विनिर्माण संयंत्र की स्थापना, ऊर्जा-कुशल तकनीकों और उन्नत ऑटोमेशन के साथ संचालन में सुधार, और बेहतर रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना। इसकी सतत विकास प्रतिबद्धता वेस्ट हीट रिकवरी, वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग और संसाधन अनुकूलन जैसी पहलों में दिखाई देती है।

---

कठिनाइयां ही इंसान को मजबूत बनाती हैं : वित्तमंत्री चौधरी

# वित्त मंत्री चौधरी ने की 66 विद्यार्थियों को 5-5 हजार स्वेच्छानुदान देने की घोषणा.....

- संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी - पद्मश्री आनंद कुमार
- मेरिट सूची में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा 1-1 लाख रुपये शिक्षा सहायता

रायपुर। संवाददाता

युवाओं के उज्ज्वल भविष्य, प्रेरणा और सुनियोजित कैरियर निर्माण के उद्देश्य से प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी के विशेष पहल पर आज रायगढ जिले के पुसौर में भव्य कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद तथा सुपर-30 के संस्थापक पद्मश्री श्री आनंद कुमार ने विद्यार्थियों को सफलता के मंत्र दिए। कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने 66 चयनित विद्यार्थियों को 5-5 हजार रुपये स्वेच्छानुदान प्रदान करने की घोषणा की। इसके साथ ही कहा कि आगामी वर्ष कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं की मेरिट सूचियों में स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को 1-1 लाख रुपये शिक्षा सहायता दिया जाएगा। कार्यक्रम में सर्वप्रथम वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप सरकार युवाओं के भविष्य निर्माण हेतु निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि जीवन में बड़ी सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्य, सही मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत अत्यंत आवश्यक हैं। कठिनाइयाँ ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। उन्होंने अपने छात्र जीवन के संघर्षों तथा सरकारी स्कूल से कलेक्टर और मंत्री बनने की प्रेरक यात्रा साझा करते हुए कहा कि मेहनत, निर्णय शक्ति और समय के सही उपयोग से कोई लक्ष्य असंभव नहीं। उन्होंने बताया कि केवल डिग्री को महत्व देना पर्याप्त नहीं, बल्कि लक्ष्य आधारित पढ़ाई, दृढ़ संकल्प और परिस्थितियों को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही सफलता का मूल मंत्र है।

## संपादकीय

# टीबी खत्म होना था 2025 तक, लेकिन बढ़ गए डेढ़ गुना मरीज?

सन 2020 में जहां देश में टीबी के रोगियों की संख्या अठारह लाख पांच हजार छह सौ सत्तर थी, वहीं 2024 में इस संक्रामक बीमारी का शिकार होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ कर छब्बीस लाख सत्रह हजार नौ सौ तेईस हो गई। यह बेहद चिंताजनक है कि जहां देश में लक्ष्य के मुताबिक इस वर्ष तक तपेदिक को खत्म हो जाना चाहिए था, वहीं इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होती देखी जा रही है। ऐसा लगता है कि तपेदिक के उन्मूलन के लिए जो नीतिगत कसौटियां तय की गईं, उसे लागू करने को लेकर या तो लापरवाही बरती गई या फिर वे व्यावहारिक नहीं थीं। गौरतलब है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के क्षय रोग प्रभाग ने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक तपेदिक यानी टीबी रोग को खत्म करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन आज हालत यह है कि पिछले पांच वर्ष में इस रोग के मरीजों की संख्या में डेढ़ गुना की खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सन 2020 में जहां देश में टीबी के रोगियों की संख्या अठारह लाख पांच हजार छह सौ सत्तर थी, वहीं 2024 में इस संक्रामक बीमारी का शिकार होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ कर छब्बीस लाख सत्रह हजार नौ सौ तेईस हो गई। सवाल है कि टीबी रोग के उन्मूलन के लिए जो नीतियां अपनाई गईं या 'निक्षय पोषण योजना', मुफ्त दवा और इलाज की सुविधाओं जैसे उपाय किए गए, उनमें कहां कमी रह गई कि आज खत्म होने के बजाय तपेदिक के मामलों में डेढ़ गुना तक का इजाफा हो गया। तपेदिक एक संक्रामक रोग है। इसीलिए इसकी जद में आने वाले व्यक्ति के इलाज को लेकर ज्यादा संवेदनशीलता बरती जाती है। समय पर इस रोग की पहचान और उसके इलाज की शुरुआत इसके संक्रमण की आशंकाओं को कम करता है तथा मरीज के पूरी तरह ठीक होने की संभावना बनती है। इसमें जरा भी लापरवाही से न केवल किसी मरीज की स्थिति बिगड़ सकती है, बल्कि अन्य लोगों के बीच इसके फैलने का जोखिम पैदा हो सकता है। विडंबना यह है कि जागरूकता के अभाव में न केवल आम लोग इस रोग के शुरुआती लक्षणों की अनदेखी करते हैं, बल्कि इसके मरीजों के प्रति सामाजिक उपेक्षा की वजह से भी स्थिति बिगड़ती है। जाहिर है, स्वास्थ्य के मोर्चे पर बड़ी उपलब्धियों के सरकारी दावे के बरक्स जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियानों के साथ-साथ अन्य ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

**भारत को अब जिस नए तरह के आतंक का सामना करना पड़ रहा है, वह सीमा-पार से नहीं बल्कि क्लासरूम, लैब और अस्पतालों के भीतर से जन्म ले रहा है। आतंकवाद का रूप अब बदल चुका है। वह अब सीमापार की घुसपैठ, जंगलों में छिपे गिरोहों या हथियारबंद टुकड़ियों तक सीमित नहीं है बल्कि इसकी जड़ें उन सफेदपोश और शिक्षित लोगों तक पहुंच चुकी हैं, जिन्हें समाज सम्मान की दृष्टि से देखता था। आतंक का नया चेहरा वह है, जो लैब कोट पहनता है, रिसर्च पेपर लिखता है, अस्पताल में ड्यूटी करता है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है**

# गले में स्टेथोस्कोप, मन में जहर, खतरनाक है आतंकवाद का बदलता रूप

**(योगेश कुमार गोयल)**

और आईटी कंपनियों में काम करता है। यही है 'व्हाइट कॉलर टेरर', जो भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चुनौती बन गया है। 'व्हाइट कॉलर टेरर' यानी शिक्षित, तकनीकी दक्ष और समाज में सम्मानित वे लोग, जो कट्टरपंथ की डिजिटल फैक्ट्रियों में वाहक बनते जा रहे हैं।

दिल्ली के लाल किले के पास विस्फोट और डॉक्टरों के बड़े मॉड्यूल का पकड़ा जाना इस नई साजिश का सबसे भयानक संकेत है। ये न आतंकी दिखते हैं, न किसी पर संदेह होता है। लाल किले के पास कार में हुए विस्फोट में 11 लोग मारे गए और कई घायल हुए। विस्फोटक कार के चालक की पहचान जब सामने आई तो देश स्तब्ध रह गया क्योंकि वह कोई अपराधी, कोई पुराना संदिग्ध या किसी गिरोह का सदस्य नहीं बल्कि डॉक्टर था। पुलवामा का रहने वाला युवक उमर मोहम्मद उन तीन डॉक्टरों का साथी निकला, जिनके पास से फरीदाबाद में लगभग 3000 किलो विस्फोटक और हथियार बरामद हुए थे। यह कोई साधारण संयोग नहीं बल्कि एक बेहद गहरी और सुनियोजित आतंकवादी साजिश की परतें खोलने वाला तथ्य है।

डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन, ये तीनों उस गिरोह के केंद्र में थे, जो देश की राजधानी में बड़े पैमाने पर जनसंहार की योजना बना रहा था। इन सभी की प्रोफैशनल पहचान ने इतना मजबूत आवरण तैयार कर दिया था कि कोई इन्हें शक की निगाह से देख ही नहीं सकता था। इसी मॉडल का चौथा सदस्य डॉक्टर मोहिउद्दीन गुजरात पुलिस के आतंकवाद-निरोधक दस्ते की गिरफ्त में आया। चीन से मेडिसिन की पढ़ाई कर लौटे इस युवक को राइसिन जैसा घातक जहर तैयार करते हुए पकड़ा गया, जो एक ही बार में सैंकड़ों लोगों की जान ले सकता था। यह घटनाएं पहली नहीं हैं लेकिन निश्चित रूप से सबसे खतरनाक हैं। पुणे का डॉक्टर अदनान अली सरकार हो या बेंगलुरु की बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत इंजीनियर अथवा आईटी प्रोफैशनल्स, पिछले एक दशक में कई उच्च शिक्षित लोग आतंकी संगठनों के लिए काम करते हुए पकड़े जा चुके हैं। ऑनलाइन पहचान छिपाने के लिए फर्जी नाम, छद्म प्रोफाइल, एन्क्रिप्टेड चैट और डार्क वेब समूहों का इस्तेमाल अब इनका सामान्य हथियार बन चुका है। आइएस, अल-कायदा या छोटे स्थानीय मॉड्यूल, ये सभी इस नए वर्ग को अपनी 'बौद्धिक सेना' बनाने में सक्रिय हो चुके हैं।

यह धारणा अब पूरी तरह मिथ्या साबित हो चुकी है कि केवल गरीब, वंचित या अशिक्षित लोग ही मजहबी उन्माद या सामाजिक उत्पीड़न के कारण कट्टरपंथी बनते हैं। हाल के वर्षों में आतंक के रास्ते पर चलने वाले लोगों की सूची देखें तो स्पष्ट होता है कि उनमें बड़ी संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर, तकनीकी विशेषज्ञ और डिग्रीधारी युवा शामिल हैं। उनकी समस्या न तो आर्थिक है, न सामाजिक बल्कि वैचारिक है। वे इंटरनेट पर उपलब्ध कट्टरपंथी सामग्री, डार्क वेब चैट रूम, टेलीग्राम चैनलों और गहरे धार्मिक उन्माद से प्रेरित वीडियो के माध्यम से धीरे-धीरे विचलित होते हैं और फिर एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं, जिसे वे खुद भी कभी समझ नहीं पाते। भारत में केरल, कश्मीर, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं, जहां प्रोफैशनल डिग्री वाले व्यक्ति आइएस, जैश, लश्कर या अल-कायदा के लिए काम करते हुए पकड़े गए। कुछ ने तो खुद के 'जिहादी मॉड्यूल' भी बना लिए, जिनके नाम मजहबी संदर्भों से प्रेरित थे, जैसे गजवा-ए-हिंद के नाम पर सक्रिय कई छोटे समूह। ये संगठन मजहबी मान्यताओं की मनचाही व्याख्याएं करके, उसे 'धर्मयुद्ध' का रूप देकर अत्याचार, जनसंहार और हिंसा को जायज ठहराते हैं। समय-समय पर इन पर फतवे भी जारी हुए, लेकिन कट्टरपंथियों पर उनका कोई असर नहीं पड़ा।

जिहादी आतंक कोई आत्मस्फूर्त हिंसा नहीं बल्कि एक घिनौनी विचारधारा का परिणाम है। यह विचारधारा मजहबी ग्रंथों की विकृत व्याख्याओं पर आधारित है। अब जब डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक भी इस विचारधारा का शिकार होने लगें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्या कहीं गहरे छिपी है। सरकार, पुलिस और एजेंसियां अकेले इस विचारधारात्मक युद्ध को नहीं जीत सकती, यह समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। परिवारों, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक समूहों और सामाजिक नेतृत्व को मिलकर यह समझना होगा कि कट्टरपंथ कैसे जन्म लेता है और कैसे फैलता है। व्हाइट कॉलर टेरर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह संदेह के दायरे से बाहर रहता है। समाज में सम्मानित होने के कारण डॉक्टर, इंजीनियर या आईटी विशेषज्ञ कोई हथियार लेकर नहीं घूमते। वे किसी सूची में नहीं होते। उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता। वे तकनीक, बैंकिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन, एन्क्रिप्शन और साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञ होते हैं। यही कारण है कि वे निगरानी तंत्र को चकमा देने में सफल हो जाते हैं। वे वीपीएन, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन, डार्क वेब चैट, प्रोटॉन मेल और ऑटो-डिलीट चैट का इस्तेमाल करते हैं। वे विस्फोटकों की खरीद-फरोख्त के लिए फर्जी पहचान बनाते हैं। उनके खाते, उनके लेन-देन और उनकी यात्राएं सामान्य नागरिक जैसे दिखते हैं। यही कारण है कि एजेंसियों के लिए इनके व्यवहार का पैटर्न पहचानना ही सबसे कठिन चुनौती बन जाता है। आज आतंकवादी संगठनों की रणनीति बदल चुकी है। वे अब जंगलों या सीमाओं पर नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, लैब्स और तकनीकी संस्थानों में नए सदस्य खोजते हैं। टेलीग्राम और सिग्नल पर 'भाईजान', 'शहीद', 'मुजाहिद', 'काफिरों के खिलाफ जंग' जैसे भावनात्मक शब्दों में संदेश भेजे जाते हैं। ऐसे संदेश धार्मिक, सामाजिक या न्याय के नाम पर 'कथित अन्याय' का चित्र बनाते हैं और युवा धीरे-धीरे कट्टरपंथी बन जाते हैं। यह 'ब्रेन वॉशिंग' चुपचाप होती है, किसी को पता तक नहीं चलता। डॉक्टर और इंजीनियर आखिर आतंकी क्यों बन रहे हैं और आतंकवादी कौनसे नैरेटिव से प्रेरित हैं, यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। हर जिहादी संगठन अपने हिंसक कृत्यों को मजहबी मान्यताओं की आड़ में सही ठहराता है। यही कारण है कि आतंक के खिलाफ होने वाले फतवों का कोई असर नहीं होता क्योंकि समस्या धार्मिक आस्थाओं की राजनीतिक और हिंसक व्याख्याओं में है। व्हाइट कॉलर आतंकी सबसे खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि उन्हें रोकना सबसे मुश्किल है। इन पर समाज भरोसा करता है और ये विश्वास को ही हथियार बनाकर आतंक फैलाते हैं। यही कारण है कि अब भारत को सुरक्षा का एक ऐसा नया फ्रेमवर्क तैयार करना होगा, जो केवल निगरानी पर आधारित न हो बल्कि रैडिकलाइजेशन को रोकने के लिए शिक्षा, समाज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में व्यापक सुधार भी करे। बहरहाल, एजेंसियों को अब व्यवहार आधारित एआई निगरानी, डिजिटल फुटप्रिंट विश्लेषण, क्रिप्टो-ट्रैकिंग और इंटरनेशनल डेटा-शेयरिंग की दिशा में और मजबूत कदम उठाने होंगे। शिक्षण संस्थानों में साइबर-रेडिकलाइजेशन पर जागरूकता अभियान चलाने होंगे। धार्मिक नेतृत्व को कट्टरपंथी व्याख्याओं के खिलाफ स्पष्ट और ठोस संदेश देने होंगे। लाल किले का धमाका और उससे जुड़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल स्पष्ट चेतावनी है कि अगली लड़ाई जंगलों या सीमा पर नहीं होगी बल्कि क्लासरूम, लैब, अस्पताल, ऑफिस और वर्चुअल दुनिया में लड़ी जाएगी। यदि हमने इस खतरे को अभी नहीं समझा तो आतंक का यह नया चेहरा उतना ही विनाशकारी होगा, जितना हमने पहले कभी नहीं देखा। ऐसे में भारत की सुरक्षा केवल हथियारों पर नहीं बल्कि समाज के नैतिक ढ़ांचे, शिक्षण संस्थानों की जागरूकता और नागरिकों की सतर्कता पर निर्भर है।(लेखक साढ़े तीन दशक से पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार हैं)(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

## भ्रष्टाचार और जंगलराज से समझौता बना कांग्रेस की हार

**(योगेंद्र योगी )**

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने पिछले महीने आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। सीबीआई के अनुसार, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा राज्यसभा सदस्य प्रेमचंद गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता, आईआरसीटीसी अधिकारियों, कोचर ब्रदर्स समेत कुल 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए थे। यह खबर पूरे देश में पढ़ी–सुनी गई। यदि किसी ने नहीं देखी तो वह है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस ने लालू यादव के भ्रष्टाचार और जंगलराज के अन्य मामलों की तरह इसे भी नजरांदाज कर दिया। कांग्रेस यह भूल गई कि यदि ऐसे मामलों की अनदेखी की गई तो मतदाता भी उसे भूल जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में यही हुआ। मतदाता भूल गए कि कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय और प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल है। कांग्रेस ने सत्ता के लिए भ्रष्टाचार से समझौता किया। मतदाताओं ने कांग्रेस के इस रवैये को मतों से ठुकरा दिया।

सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस ने पिछली गलतियों से जरा भी सबक नहीं सीखा। भ्रष्टाचार और कानून–व्यवस्था आज भी देश में प्रमुख मुद्दा है। विकास और दूसरे मुद्दे इसकी नींव पर खड़े होते हैं, यदि नींव ही कमजोर होगी तो विकास की इबारत नहीं लिख पाएगी। कांग्रेस ने बिहार में लालू यादव की पार्टी से सत्ता के लिए समझौता कर अपने पैरों पर फिर से कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। कांग्रेस को बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से मात्र 6 सीटें मिली। इस शर्मनाक हार की जिम्मेदार खुद कांग्रेस है। कांग्रेस अब इस जिम्मेदारी से भागने के लिए फिर से वही पुराना वोट चोरी, सरकारी मशीनरी के चुनाव में दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। अभी भी कांग्रेस इस सच्चाई का सामना करने को तैयार नहीं है कि उसने एक महाभ्रष्ट लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से सीटों का समझौता करके भारी भूल की है। बिहार के मतदाताओं ने इन दोनों दलों को तगड़ा सबक सिखाया है।

कांग्रेस ने आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे लालू परिवार के जरिए चुनावी वैतरणी पार करने का गलत निर्णय लिया। यह जानते हुए भी कि मतदाता इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपराधी परिवार के साथ चुनावी तालमेल की कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ गई। भाजपा और मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने लालू यादव के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार और जंगलराज को प्रमुख मुद्दा बनाया। कांग्रेस इसके बचाव में कोई दलील देकर मतदाताओं को संतुष्ट नहीं कर सकी। बिहार में चुनाव हो और चारा घोटाले से जुड़ी कहानियां सामने न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये घोटाला ही ऐसा था कि 30 साल बाद भी लोग इसके बारे में बात करते हैं और जानने की चाहत रखते हैं। कांग्रेस ने 950 करोड़ रुपये के घोटाले में अपने प्रमुख सहयोगी और राजद प्रमुख लालू प्रसाद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए पर्दे के पीछे से राजनीतिक चालें चलीं, लेकिन वे असफल रहीं। वर्ष 1990-96 के दौरान सामने आया चारा घोटाला बिहार पशुपालन विभाग में हुआ। इसमें अधिकारियों ने बेईमान सप्लायर्स के साथ मिलकर फर्जी बिलों के आधार पर सैकड़ों करोड़ रुपये का गबन किया। जांच में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, नौकरशाहों और राजनेताओं की संलिप्तता सामने आई। ये सरकारी खजाने की बड़ी लूट थी।

यह घोटाला मुख्य रूप से 1990 के दशक में हुआ। इस समय लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। इसका खुलासा 1996 में तब हुआ, जब चाईबासा (अब झारखंड में) के उपायुक्त अमित खरे ने पशुपालन विभाग के दफ्तरों पर छापा मारा और फर्जी बिलों के जरिए धन निकासी की गड़बड़ी पकड़ी। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव को पांच मामलों में दोषी ठहराया गया। लालू प्रसाद यादव पशुपालन घोटाले के मामलों में लालू अब तक कुल सात बार जेल जा चुके हैं। चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में 3 अक्टूबर 2013 को पहली बार उन्हें सजा मिली थी। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, जगदीश शर्मा, आर.के. राणा जैसे नेताओं और अफसरों को भी इस मामले में सजा सुनाई गई। कांग्रेस ने लालू राज की इस सच्चाई को जानने के बावजूद राजनीतिक पैतरेबाजी से बिहार में सत्ता हासिल करने का नाकाम प्रयास किया। बिहार में वोट चोरी का अभियान चलाया गया। यह कभी चुनावी मुद्दा नहीं रहा।कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक भी नजीर पेश नहीं कर सकी। कांग्रेस यदि गंभीर होती तो अपने शासित राज्यों में किसी एक का उदाहरण देकर मतदाताओं को विश्वास दिला सकती थी, कि वह भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस की नीति पर अमल करती है। कांग्रेस को यह समझना होगा कि राजद जैसे दागदार क्षेत्रीय दलों की तुलना वह एक प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी है। सिर्फ एक राज्य में सत्ता के लिए भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से समझौता करने की भारी कीमत पूरे देश में चुकानी पड़ सकती है। यही कीमत दूसरे राज्यों के अलावा अब कांग्रेस ने बिहार में चुकाई है।(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

# शराब की लुभावनी पैकेजिंग के खतरे एवं सुप्रीम कोर्ट की चिंता

**(ललित गर्ग )**

सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए चिंता जताई है कि शराब की बोतलों की पैकिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उपभोक्ता को उसकी वास्तविक हानियों से दूर ले जाए। चेतावनियां अक्सर बोतल के किनारे इस तरह लगाई जाती हैं कि वे दिखती ही नहीं। कंपनियां स्वास्थ्य चेतावनियों को ढककर अपने उत्पाद की सुंदरता को आगे करती हैं।

हाल ही में देश की शीर्ष अदालत ने शराब की पैकेजिंग को लेकर जो गंभीर टिप्पणी की है, वह केवल कानूनी हस्तक्षेप नहीं बल्कि सामाजिक चेतना को झकझोरने वाली चेतावनी है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि शराब को इस तरह आकर्षक और लुभावना बनाकर प्रस्तुत करना सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ-साथ संस्कृति एवं सामाजिक के साथ खिलवाड़ है। चमकीली बोतलें, विदेशी डिजाइन, चटकदार रंग और ग्लैमरस बॉक्स-ये सब रणनीतियां लोगों को, विशेषकर युवाओं को, महिलाओं को शराब की ओर खींचने का साधन बन चुकी हैं। शराब की यह भ्रामक एवं बाजारवादी पैकेजिंग एक गंभीर एवं नया खतरा है। यह प्रवृत्ति केवल बाज़ार का विस्तार नहीं बल्कि पूरे समाज के स्वास्थ्य, नैतिकता और मानसिक संतुलन पर गहरा हमला है। जन-स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली शराब कम्पनियों की दुराग्रही सोच एवं गुमराह करने वाली पैकिंग एक आपराधिक कृत्य है। जूस पैक जैसे दिखने वाले टेट्रा पैक में बेची जा रही शराब अनेक खतरों को आमंत्रण है।

आज जब देश शराब की वजह से होने वाली बीमारियों, दुर्घटनाओं, हिंसा, पारिवारिक विघटन और मानसिक अवसाद जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, तब शराब को 'फैशनेबल' बनाकर बेचना एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। शराब कंपनियों ने पैकेजिंग को आधुनिकता, प्रतिष्ठा और स्टाइल से जोड़ दिया है, जिससे युवा वर्ग इसे किसी उपलब्धि जैसा मानने लगा है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से यह पैकेजिंग व्यक्ति के मन में यह भ्रम पैदा करती है कि शराब पीना आधुनिकता का प्रतीक है, जबकि वास्तविकता यह है कि शराब हर रूप में शरीर और मन के लिए घातक ज़हर है। शराब के घातक एवं दुष्प्रभाव किसी से छिपे नहीं हैं। यह धीरे-धीरे शरीर को भीतर से खोखला करते हुए नशे की अंधी गलियों में धकेल देती है। लिवर सिरोसिस, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, कैंसर, मानसिक असंतुलन, अवसाद और नींद की गंभीर समस्याएं शराब सेवन की सीधी देन हैं। सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले हजारों लोग शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण अपनी जान गंवाते हैं। घरेलू हिंसा, अपराध और परिवारों के टूटने में शराब की भूमिका लंबे समय से प्रमाणित है। ऐसे में शराब को आकर्षक पैकेजिंग में परोसना मानो लोगों को स्वेच्छा से विनाश के रास्ते पर भेजने जैसा है।

सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए चिंता जताई है कि शराब की बोतलों की पैकिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उपभोक्ता को उसकी वास्तविक हानियों से दूर ले जाए। चेतावनियां अक्सर बोतल के किनारे इस तरह लगाई जाती हैं कि वे दिखती ही नहीं। कंपनियां स्वास्थ्य चेतावनियों को ढककर अपने उत्पाद की सुंदरता को आगे करती हैं। यह न केवल अनैतिक है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी नीतियों की मूल भावना के भी विरुद्ध है। जब सरकार तंबाकू पर बड़ी और भयावह चेतावनियों को अनिवार्य कर चुकी है, तो शराब जिसका स्वास्थ्य पर प्रभाव कई मामलों में उतना ही विनाशकारी है, उसकी पैकेजिंग पर भी समान कठोर नियम लागू होना चाहिए। समाज में शराब की बढ़ती स्वीकृति का बड़ा कारण यह भी है कि शराब उद्योग ने पैकेजिंग को ही आकर्षक विज्ञापन का माध्यम बना दिया है। जहां शराब विज्ञापन पर कानूनी रोक है, वहां कंपनियां रंगीन बोतलों और खूबसूरत बॉक्सों को ही प्रचार का तरीका बना लेती हैं। यह परोक्ष विज्ञापन है, जो कानून की भावना का उल्लंघन करता है और युवाओं को नशे की ओर ले जाता है। ऐसे में सादे, सरल और सामान्य पैकेजिंग की दिशा में कदम बढ़ाना आवश्यक है, ताकि शराब किसी 'लक्ज़री उत्पाद' की तरह न दिखे, बल्कि उसका स्वरूप ही लोगों को चेतावनी देने वाला बने।

यह भी चिंताजनक है कि शराब उद्योग का उद्देश्य केवल बिक्री बढ़ाना है, भले ही उससे समाज कितना भी प्रभावित क्यों न हो। वे यह नहीं देखते कि शराब कितने घर बर्बाद कर रही है, कितने लोग बीमार हो रहे हैं और कितनी जिंदगियां संकट में हैं। इस मानसिकता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बेहद आवश्यक है। शराब की ग्लैमरस पैकेजिंग पर रोक लगाने से न केवल उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि समाज में नशामुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण वातावरण भी बनेगा। सरकारों के लिये राजस्व का बड़ा जरिया शराब है, इसलिये सरकारें भी शराब के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट की इस चेतावनी को केवल उद्योगों के लिए ही नहीं, बल्कि सरकार, समाज और परिवारों के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जाना चाहिए। शराब किसी भी रूप में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उसे आकर्षक बनाकर बेचना मानव जीवन के मूल्य को कम करना है। आज आवश्यकता है कि शराब की पैकेजिंग को नियंत्रित किया जाए, उसे सामान्य और गैर-आकर्षक बनाया जाए, स्पष्ट चेतावनियां लिखी जाएं और शराब को समाज में सम्मानजनक स्थान देने वाली प्रवृत्तियों पर रोक लगे। सरकार को भी स्वस्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ऐसे कानून बनाने चाहिए जो शराब उद्योग की विपणन चालों को सीमित करें।

चिंता का विषय यह भी है कि शराब अब केवल बार या नाइट क्लबों तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक अवसरों-शादियों, जन्मदिनों, दफ्तर की पार्टियों, त्योहारों, यहां तक कि छोटे सामाजिक समारोहों में भी परोसी जाने लगी है। शराब को 'सामाजिकता का हिस्सा' और 'आधुनिकता का प्रतीक' बताकर जिस तरह से उसकी पैठ बढ़ाई जा रही है, वह एक खतरनाक सांस्कृतिक परिवर्तन का संकेत है। परिवारों में युवा पीढ़ी अपने बड़ों को शराब का उपभोग करते हुए देखकर इसे सामान्य मानने लगी है, जिससे किशोर अवस्था में ही शराब सेवन की शुरुआत हो जाती है। स्कूल-कॉलेज के छात्र फैशन, दबाव, दोस्तों की नकल और विज्ञापन जैसी पैकेजिंग के प्रभाव में आकर शराब की लत में डूब रहे हैं। यह पीढ़ी मानसिक एवं शारीरिक दोनों स्तर पर कमजोर होती जा रही है। शराब न केवल उनकी पढ़ाई, कैरियर एवं सोचने-समझने की क्षमता को नष्ट करती है, बल्कि भविष्य के परिवार एवं समाज की नींव तक को हिला देती है। इन बढ़ती चिन्ताओं का समाधान केवल कानून से नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता, सांस्कृतिक पुनर्संयम और परिवारों में जिम्मेदार व्यवहार से ही संभव है। समाज तभी सुरक्षित हो सकता है जब हम शराब को आकर्षण का नहीं, विनाश का प्रतीक मानें। उसकी पैकेजिंग में चमक-दमक नहीं, चेतावनी झलके। उसका सेवन आधुनिकता नहीं, दुर्बलता समझा जाए। यह चेतना तभी बढ़ेगी जब कानून भी कठोर होंगे और समाज भी सजग। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी इसी दिशा में एक गंभीर कदम है, अब सरकार और समाज की जिम्मेदारी है कि इसे वास्तविक सुधार में बदला जाए। लेखक, पत्रकार, स्तंभकार है। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

# खरीदी केन्द्रों में बारदाना उपलब्ध सुनिश्चित करें, किसी भी समिति में बारदानों कमी नहीं होनी चाहिए : कलेक्टर हरिस एस

## विभिन्न विभाग एसआईआर के कार्य में आवश्यक करें सहयोग

**जगदलपुर।** कलेक्टर हरिस एस ने कहा कि धान खरीदी व्यवस्था के सुचारू संचालन पर विशेष ध्यान देवें।खरीदी केन्द्रों के सभी नोडल अधिकारी बारदाना उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, किसी भी समिति में बारदानों कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही संग्रहण केन्द्रों में स्टैगिंग की व्यवस्था को निर्धारित मानक के अनुरूप सुव्यवस्थित किया जाए। उन्होंने कहा कि पीडीएस दुकानों से बारदाना वापस जमा करवाया जाए। संवेदनशील खरीदी केंद्रों में निगरानी बढ़ाई जाए और सीमावर्ती क्षेत्रों व बड़े किसानों पर विशेष ध्यान रखा जाए। कलेक्टर हरिस एस ने मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर जिले में चल रहे प्रमुख विकासात्मक, प्रशासनिक और कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने खरीदी केन्द्रों में गेट पास ऐप, सतर्क ऐप का उपयोग करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा अपनी जमीन

का पूरा खसरा को जोड़वाने के लिए (यूएफआर के तहत की जानकारी को अपडेट) एग्रिस्टैक के माध्यम से सीएससी सेंटर से या सोसायटी में जाकर जुड़वा सकते हैं ।इसकी भी जानकारी भी दिया जाए। किसानों का रकबा समर्पण की प्रक्रिया समितियों के माध्यम से करवाने कहा। टोकन व्यवस्था, फिजिकल वेरिफिकेशन और चेक पोस्ट की निगरानी को सुदृढ़ करने निर्देशित किया। कलेक्टर ने कहा कि जिले में एसआईआर के कार्य किया जा रहा इसमें बीएलओ को विभिन्न विभागों के अधिकारियों और मैदानी अमलों द्वारा फॉर्म भरवाने, डिजिटाइजेशन कार्य में आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करें, उन्होंने ग्राम सचिव तथा रोजगार सहायकों को आवश्यकता अनुसार वालिंटियर के रूप में सहयोग करने हेतु निर्देशित किया। बैठक में शासन के निर्देशानुसार आधार कार्ड आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति, जेम पोर्टल से खरीदी के संबंध में चर्चा किया गया। इसके अलावा बैठक में एनसीईआर रिपोर्ट की चर्चा करते हुए कहा कि मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के समन्वय से स्कूली बच्चों के आधार कार्ड बनवाने की पहल तेज करने निर्देश दिए गए। 0-5 वर्ष के बच्चों का आधार सेचुरेशन करवाने पर बल दिया गया। पिछले पाँच वर्षों में अस्पतालों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्रों का उपयोग आधार एवं जाति प्रमाण पत्र के लिए करने पर भी चर्चा हुई। आयुष्मान कार्ड बनाने,एसबीएम शौचालयों की रिवेरीफि केशन की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के आयुष्मान कार्ड, मोतियाबिंद जांच एवं उपचार, स्वास्थ्य केंद्र भवनों की स्थिति , कृषि विभाग के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वारिसन का नामांतरण, एग्री-स्टैक एवं पंजीयन की स्थिति, किसान क्रेडिट कार्ड के लक्ष्य अनुरूप प्रगति, शिक्षा विभाग से आपार आईडी, स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र की समीक्षा किए ।बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत अपूर्ण कार्यों की प्रगति, लोक निर्माण विभाग, ब्रिज एवं सेतु निर्माण, जल संसाधन विभाग के कार्यों की अद्यतन स्थिति, जेम पोर्टल से खरीदी का जिला स्तरीय समिति द्वारा सत्यापन कर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन, अपर कलेक्टर सी पी बघेल सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

## जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में मॉडल आपदा प्रबंधन योजना के सुदृढ़ क्रियान्वयन की शुरुआत

**दंतेवाड़ा।** जिला अस्पताल में मॉडल आपदा प्रबंधन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं यूनिसेफ के सहयोग से महत्वपूर्ण गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। विगत वर्ष हेल्थ सिस्टम ईमर्जन्सी प्रिपेरेडनेस विषय पर राज्य एवं संभाग स्तर पर व्यापक प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जिसके आधार पर चयनित 7 जिलों में अस्पताल आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया, जिनमें दंतेवाड़ा जिला भी शामिल है। मॉडल एचडीएमपी को व्यावहारिक रूप से लागू करने हेतु यूनिसेफ द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ मती वंदना चौहान को जिलों के भ्रमण हेतु आमंत्रित किया गया है, जो अस्पतालों को हैंड होल्डिंग, मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहायता प्रदान इसी क्रम में जिला अस्पताल में एक बहु-विभागीय बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें अग्निशमन विभाग, विद्युत विभाग और पीडब्ल्यूडी के सदस्यों को शामिल रहे।

## उपार्जन केन्द्रों में कृषकों के अनिवार्यत: फोटो लेने रकबा समर्पण के संबंध में कलेक्टर ने दिए निर्देश

**दंतेवाड़ा।** जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय सीमा बैठक का आयोजन कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में कलेक्टर ने सर्वप्रथम समर्थन मूल्य में धान खरीदी की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी किसानों से प्राथमिकता से टोकन काट कर खरीदी किए जाए। इसके अलावा कृषकों के गेट पास और सभी किसानों के अनिवार्यतः फोटो भी लेना सुनिश्चित करें। ताकि वास्तविक किसान की ही धान खरीदी की जा सके। उन्होंने धान खरीदी के लिए अनावरी रिपोर्ट को समितिवार और ग्राम वॉर एंट्री करने कहा गया ताकि कृषकों के वास्तविक उपज धान की ही खरीदी हो। उन्होंने सभी समिति और उपार्जन केंद्र के द्वारा किसानों के धान बिक्री के पश्चात अनिवार्य रूप से रकबा समर्पण कराने और किसान पंजीयन के अपूर्ण, अप्राप्त व्यक्तिगत जानकारी को शीघ्रता से पूर्ण करने को कहा। इस क्रम में उनके द्वारा जिले में धान खरीदी अवधि के दौरान अवैध धान परिवहन, खरीदी बिक्री को रोकने हेतु मंडी अधिनियम के अधीन

कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। समय सीमा बैठक में कलेक्टर द्वारा उद्योग, जनपद पंचायत, श्रम तथा लीड बैंक अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार मेले के तहत शत प्रतिशत संतृप्तिकरण करने हेतु निर्देशित करते हुए कहा कि इस अभियान में युवाओं एवं स्व सहायता समूहों को प्राथमिकता में रखते हुए उपरोक्त संबंधित विभाग आपसी समन्वय बना कर लक्ष्यापूर्ति करें।

**कलेक्टर द्वारा अमीन पटवारी परीक्षा हेतु जारी किए गए दिशा निर्देश**-समय सीमा बैठक में कलेक्टर ने आगामी 7 दिसंबर को आयोजित होनी वाली अमीन भर्ती परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने कहा गया है कि प्रत्येक अभ्यर्थी तक ये निर्देश समय पर पहुंचें। f

नर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों को परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र का अवलोकन करना अनिवार्य होगा, ताकि परीक्षा दिवस पर किसी प्रकार की परेशानी न आए। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम दो घंटे पहले उपस्थित होना होगा, जिससे फ्रिस्किंग और फोटोयुक्त पहचान पत्र से सत्यापन की प्रक्रिया में आसानी रहे।

## जिले में धान के साथ-साथ देवा मांडवी ने मिलेटस फसल 'बड़ा कोसरा' को बनाया लाभदायक खेती

**दंतेवाड़ा।** जिले में पारंपरिक धान उत्पादन के साथ-साथ अब अन्य मिलेट फसलों जैसे रागी, कुल्थी, कोदो, मंडिया, कोसरा में भी वैज्ञानिक और नवाचार आधारित खेती का विस्तार तेजी से हो रहा है। इस क्रम में दुरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में ''बड़े कोसरा'' की फ सल नई तकनीकों के साथ मजबूती से उभरी है और किसानों के लिए लाभकारी विकल्प बन रही है। इस तरह ग्राम पोटाली, पटेलपारा (विकासखंड कुआकोंडा) के मेहनती किसान देवा मांडवी जिले की उभरती कृषि क्रांति का प्रेरक चेहरा बनकर सामने आए हैं। एसएमआई तकनीक को अपनाकर मांडवी ने बड़ा कोसरा की खेती में एक सफल मॉडल प्रस्तुत किया है, जो जिलेभर के किसानों के लिए मिसाल है। निर्माण ऑर्गेनाइजेशन दंतेवाड़ा और कृषि विभाग की तकनीकी सहायता ने इस प्रयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 15-21 दिन की नर्सरी, 30-30 सेंटीमीटर की दूरी पर एकल पौध रोपण, नियमित साइकिल वीडिंग तथा जीवामृत एवं हांडी दवा जैसे जैविक उपचारों को अपनाया। वर्तमान में उनके

कृषि फार्म में अगस्त को रोपी गई फसल आज प्रति पौधा 30-40 स्वस्थ बालियों के साथ लहलहा रही है। मालूम हो कि देवा मांडवी को पिछले वर्ष अरकू (आंध्र प्रदेश) में हुए प्रशिक्षण तथा फसल भ्रमण ने आधुनिक खेती की नई समझ दी, जिसे उन्होंने तुरंत खेत में लागू किया। आज उनका खेत ''मॉडल फार्म'' के रूप में ग्राम पोटाली की पहचान बन चुका है। इसमें निर्माण संस्था, कृषि विभाग और जि ला प्रशासन ने पूरे प्रक्रिया में मार्गदर्शन प्रदान किया। मांडवी बताते है कि उन्होंने एसएमआई तकनीक से बड़ा कोसरा की खेती शुरू की और आज इसका बेहतरीन परिणाम हमारे सामने है। निर्माण संस्था, कृषि विभाग और जिला प्रशासन से मिली तकनीकी सहायता ने मुझे नई दिशा दी। मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के और किसान भी इस विधि को अपनाकर अपनी खेती को मजबूत और लाभदायक बनाएं। जिले के अन्य क्षेत्र जैसे छिंदनार, बुधपदर, पालनार, भटपाल, गुटोली, गुमलनार, बड़े गुडरा, मोखपाल, बड़े तुमनार, छोटे तुमनार, बुरगुम, अचेली, बालूद, गंजेनार, पाहुरनार आदि क्षेत्रों में भी एसएमआई विधि से कोसरा की सफल रोपाई जारी है। भूमगादी समिति द्वारा किसानों को कोसरा चोप उपलब्ध कराया गया है। निर्माण संस्था के फील्ड ऑफिसर सुरेश कुमार नाग तथा स्थानीय संसाधन व्यक्ति (एलआरपी) लगातार तकनीकी मार्गदर्शन दे रहे हैं।

## 3 कंप्यूटर ऑपरेटर की रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 4 दिसंबर को होगा वाक इन इंटरव्यू

**दंतेवाड़ा।** जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज से जारी विज्ञप्ति अनुसार दंतेवाड़ा जिले के विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं अन्य जनदर्शन, जन शिकायत, जन चौपाल अन्तर्गत प्राप्त आवेदनो के समन्वय एवं निराकरण हेतु कार्य, विभागीय समन्वय एवं हितग्राहियों से सम्पर्क किये जाने के अलावा डाटा एनालिसिस का कार्य हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती की जानी है। उक्त कार्य संचालन किये जाने हेतु 03 कम्प्यूटर आपरेटर की आवश्यकता है। इनकी भर्ती वाक-इन इंटरव्यू, के माध्यम से की जावेगी।

इसके शैक्षणिक योग्यता के अनुसार 12 वी कक्षा उत्तीर्ण, कम्प्युटर का ज्ञान, पीजीडीसीए या डीसीए, कौशल विकास योजना अन्तर्गत डाटा एन्ट्री आपरेटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अनिवार्य किया गया है। साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया में जिले के स्थानीय अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी। अभ्यर्थी को हिन्दी, गोंडी, एवं हल्बी भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। इस संबंध में वाक इन इंटरव्यू की तिथि 04 दिसंबर 2025 को प्रातः 10 बजे जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज दंतेवाड़ा में आयोजित किया जावेगा। आवेदन पंजीयन का समय प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक, दस्तावेज सत्यापन का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक, तथा साक्षात्कार का समय दोपहर 2 बजे से 5.30 बजे तक नियत की गई है।इसके लिए आवेदकों को निर्देशित किया गया है कि वे शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव संबंधी सम्पूर्ण दस्तावेज की मूल प्रति के साथ एक सेट प्रतिलिपि के साथ उपस्थित होवे। विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाईट www.dantewada.gov.in तथा कार्यालय के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है।

## मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई में रिक्त पदों की भर्ती हेतु 15 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित

**दंतेवाड़ा।** कार्यालय महिला बाल विकास विभाग से जारी विज्ञप्ति अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वीकृत मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों एवं स्वीकृति अनुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई के जिला बाल संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, आउटरीच वर्कर की संविदा पदों पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से दिनांक 15 दिसंबर 2025 तक आवेदन आमंत्रित है। उक्त पदों पर भर्ती के लिये आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग दंतेवाड़ा को प्रेषित किया जाना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

## चारो विकासखण्डों में ''एआई स्टीम लैब'' स्थापित एवं प्रशिक्षण हेतु निविदा आमंत्रित

**दंतेवाड़ा।** जिला शिक्षा कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले के चारो विकासखण्डों के अंतर्गत 04 शासकीय हाई स्कूल पोटाकेबिन चितालूर, गुमड़ा, कुआकोण्डा 01 एवं मोखपाल में एआई स्टीम लैब स्थापित एवं प्रशिक्षण व क्रियान्वयन किया जाना है। इस संबंध में निविदा प्रपत्र जिला शिक्षा कार्यालय से आवेदन प्रस्तुत कर रूपये 1000 ( एक हजार रूपये मात्र) का नगद भुगतान कर दिनांक 22 दिसंबर 2025 के पूर्व कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किये जा सकते है। इसके के लिए अधिकृत इच्छुक फ र्म से सील बंद दो पृथक-पृथक लिफाफे में आवश्यक दस्तावेज सहित रजिस्ट्री डाक, स्पीड पोस्ट एवं स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी।

## 4 तहसीलदारों और 2 सीएमओ को सीएसआर प्रक्रिया में धीमी प्रगति पर दिया गया शोकाज नोटिस

**दंतेवाड़ा।** भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर के निर्देशों के अनुरूप विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 का कार्य जिले में प्रगतिशील है। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार गणना पत्रक का डिजिटाइज्ड (डिजिटल रूपांतरण) कार्य समय-सीमा में पूर्ण करना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर कुणाल दुदावत द्वारा प्रतिदिन शाम 6.00 बजे गणना पत्रक के डिजिटाइजेशन की प्रगति की समीक्षा हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। विगत 24 नवंबर 2025 को आयोजित समीक्षा बैठक में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की प्रगति अत्यंत कम पाई गई। इसके तहत कटेकल्याण तहसीलदार का प्रतिशत 43.67, दंतेवाड़ा 48.24, बड़े बचेली 44.41, कुआकोंडा 43.13 तथा नगर पंचायत गीदम में मुख्य नगरपालिका अधिकारी का प्रतिशत 49.62 और दंतेवाड़ा का 44.85 दर्ज किया गया। यह आंकड़े अपेक्षाकृत कम होने से कलेक्टर ने नाराजगी प्रकट करते हुए स्पष्ट कहा कि संबंधित अधिकारी गणना पत्रकों के डिजिटाइज्ड कार्य को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जो निर्वाचन कार्य में लापरवाही तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना को दर्शाता है। इसके साथ ही उन्होंने उपरोक्त अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

## विवाहित महिला मतदाताओं के सत्यापन की चुनौती को बीएलओ ने किया पार

**जगदलपुर।** चुनावी प्रक्रिया में सटीकता और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर हरिस एस ने सोमवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दो बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को सम्मानित किया। यह सम्मान मतदाताओं के शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन के असाधारण लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदान किया गया है। कलेक्टर हरिस एस द्वारा सराहे गए अधिकारियों में जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजापुट मतदान केंद्र के बीएलओ एमके राणा शामिल हैं, जिन्होंने अपने केंद्र के 646 मतदाताओं का शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा किया है। वहीं चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के बड़े किलेपाल-1 मतदान केंद्र के बीएलओ बोमड़ा राम मंडावी को भी उनके प्रशंसनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने केंद्र के 782 मतदाताओं का शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन सुनिश्चित किया है।

### धैर्य और तकनीक से किया मुश्किल कार्य आसान

कलेक्टर ने दोनों अधिकारियों के समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका यह कार्य न केवल मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाएगा, बल्कि अन्य अधिकारियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगा। अपने अनुभव साझा करते हुए, सम्मानित बूथ स्तरीय अधिकारियों ने बताया कि इस जटिल कार्य में सबसे बड़ी चुनौती शादी के उपरांत उनके क्षेत्र में नए पते पर निवासरत महिला मतदाताओं का सत्यापन करना था। पुरानी जानकारी के अभाव में यह कार्य कठिन था, किंतु धैर्यपूर्ण और मिलनसार व्यवहार से यह कार्य आसान हो गया। उन्होंने बताया कि महिला मतदाताओं के पूर्व में निवासरत पते के आधार पर सारी जानकारी ऑनलाइन निकालकर इस सत्यापन कार्य को तीव्रता से और सटीकता के साथ पूरा किया गया। बूथ स्तरीय अधिकारियों के विनम्र व्यवहार के कारण ही ग्रामीणों का भी इस महत्वपूर्ण कार्य में भरपूर और सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। इस प्रकार, समर्पण, तकनीक और बेहतर नागरिक संवाद के समन्वय से इन अधिकारियों ने मतदाता सूची पुनरीक्षण के एक महत्वपूर्ण चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया।

# कलिंगा सोशल वेलफेयर के तत्वाधान में बैलाडीला कबड्डी कप का हुआ शुभारम्भ, विधायक हुए शामिल

**किरंदुल।** लौहनगरी किरंदुल में संचालित समाजसेवी संस्था कलिंगा सोशल वेलफेयर समाजसेवी संस्था के तत्वाधान में प्रति वर्ष की ही भांति इस वर्ष भी किरंदुल के प्रकाश विद्यालय के ग्राउंड में संभाग स्तरीय बैलाडीला कब्बडी कप 2025 का आगाज हुआ। कब्बडी टूर्नामेंट के शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दंतेवाड़ा विधायक चेत राम अट्टामी,विशेष अतिथि के रूप में किरंदुल पालिकाध्यक्ष रूबी सिंह,जिला पंचायत सदस्य सोमारू कड़ती,किरंदुल थाना प्रभारी संजय यादव,पूर्व पालिकाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ,सीएमओ किरंदुल पालिका शशि भूषण महापात्रा ,किरंदुल भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सोढ़ी ,मंडल महामंत्री विक्रम नाहक ,बैलाडीला प्रेस क्लब के महासचिव अरुण शर्मा ,वरिष्ठ

पत्रकार आर के बैरागी रहें।बैलाडीला कब्बडी कप के टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच की अध्यक्षता संयोजक श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला दंतेवाड़ा एवं बैलाडीला प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेंद्र सक्सेना ने की।इस दौरान मुख्य अतिथि के करकमलों से टूर्नामेंट के निर्णायक मंडल के सदस्यों को कैप और टी शर्ट भेंट कर सम्मानित किया। एनजीओ कलिंगा सोशल वेलफेयर संस्था के तत्वावधान में होनी वाली संभाग स्तरीय कब्बडी प्रतियोगिता में सम्पूर्ण बस्तर संभाग की टीमों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। स्वागत भाषण कलिंगा सोशल वेलफेयर संस्था के अध्यक्ष रवि दुर्गा और महासचिव किशोर जाल ने किया। मंच संचालन कलिंगा सोशल

# जिले में 0 से 5 वर्ष के बच्चों के आधार पंजीयन के लिए होगा ग्राम-स्तरीय विशेष शिविरों का आयोजन

**जगदलपुर।** जिला प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 0 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का शत-प्रतिशत आधार पंजीयन सुनिश्चित करने हेतु ग्राम स्तर पर विशेष आधार शिविरों के आयोजन किया जाएगा।

कलेक्टर हरिस एस द्वारा इन शिविरों के सुचारू संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सबसे पहले सचिव और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्वे के अनुसार वंचित 0-5 वर्ष के हितग्राहियों (बच्चों) की सूची तैयार कर जनपद पंचायत और जिला कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। सूची बनाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है। जिन बच्चों का ऑनलाइन या ऑफलाइन जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनाकर उपलब्ध कराया जाए। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में माता-पिता का नाम उनके आधार कार्ड में दर्ज नाम के समान हो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र की प्रति हितग्राहियों के अभिभावकों को उपलब्ध करानी होगी। शिविर के सफ ल क्रियान्वयन हेतु आयोजन से दो दिन पूर्व संबंधित ग्राम में कोटवार के माध्यम से शिविर स्थल एवं दिनांक के संबंध में मुनादी कराई जाएगी। शिविर स्थल पर बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन, हितग्राही और उनके अभिभावकों को बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र और अभिभावक के आधार कार्ड के साथ उपस्थित होने के लिए निर्देशित करेंगे। सर्वे सूची के अनुसार जिस ग्राम में 0-5 वर्ष के बच्चों की संख्या सर्वाधिक होगी, सर्वप्रथम आधार शिविर वहीं आयोजित किया जाएगा और शत-प्रतिशत पूर्ण होने तक इसका संचालन उसी ग्राम में जारी रहेगा। शिविरों के संचालन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा रोस्टर के अनुसार ग्रामीण डाक सेवक की ड्यूटी लगाई जाएगी। शिविरों की प्रगति का अवलोकन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जाएगा।

आधार पंजीयन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी सेक्टर सुपरवाइजर एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'अ' (आधार पंजीयन की जानकारी) और प्रपत्र 'ब'(वापस किए गए हितग्राहियों की जानकारी) में भरी जाएगी। इन प्रपत्रों की एक कॉपी संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी एवं जनपद पंचायत को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

प्रपत्र 'ब' में विशेष रूप से उन कारणों को दर्ज किया जाएगा जिनके चलते पंजीयन नहीं हो सका, जैसे- जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होना, जन्म प्रमाण पत्र में माता-पिता का नाम आधार कार्ड के अनुसार दर्ज न होना, या जन्म प्रमाण पत्र का ऑफलाइन जारी होना शामिल है।

## संक्षिप्त समाचार

### महाप्रबंधक के नेतृत्व में सामूहिक प्रस्तावना वाचन के साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में संविधान दिवस श्रद्धा व संकल्प के साथ मनाया गया



**बिलासपुर।** 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, जिसे 26 जनवरी, 1950 को देश में लागू किया गया । इसी महान संविधान की शक्ति और मार्गदर्शन से आज भारत पूरे विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित है । इसी क्रम में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में आज संविधान दिवस का गरिमापूर्ण आयोजन आज दिनांक 26 नवंबर 2025 को किया गया । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, मुख्यालय परिसर, बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया । तत्पश्चात सभी विभागाध्यक्षों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने एकजुट होकर प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक सहित सभी विभागाध्यक्ष, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे । इसी प्रकार रायपुर, बिलासपुर और नागपुर मंडलों में भी मंडल रेल प्रबंधकों के नेतृत्व में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रस्तावना का वाचन कर संविधान दिवस की गरिमा को चरितार्थ किया ।

### उत्कृष्ट कार्य करने वाले 13 बीएलओ को कलेक्टर ने किया सम्मानित

**बिलासपुर।** 26 नवम्बर 2025 को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य में शत प्रतिशत डिजिटाईजेशन व उत्कृष्ट कार्य करने पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कलेक्टर कार्यालय में आज 13 बीएलओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गहन पुनरीक्षण कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर विधानसभा क्षेत्र कोटा के बीएलओ श्रवण कुमार यादव, श्रीमती अमरिका बाई, श्रीमती शैल जगत, तखतपुर की श्रीमती रेणु खांडे, मस्तुरी की श्रीमती खेमतला, श्रीमती शारदा ओरकेरा, दिनेश कुमार भारती, श्रीमती उर्वशी जगत, श्रीमती संतोषी मरकाम, श्रीमती सुकृता पावले, बिल्हा की नीली डहरिया, बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ प्रशांत शर्मा, अवधेश विमल को सम्मानित किया। इन सभी बीएलओ ने मतदाता पुनरीक्षण के अंतर्गत गणना पत्रक वितरण, पत्रक भरवाने, प्राप्त फॉर्म की पूर्ण संग्रहण और उनके ऑनलाईन एंट्री जैसे महत्वपूर्ण चरणों को दक्षता और समयबद्धता के साथ शत प्रतिशत पूरा किया।

### गोलबाजार में ट्रैफिक अभियान के दौरान एएसपी और व्यापारियों में तीखी बहस, वीडियो वायरल

**बिलासपुर।** न्यायधानी के गोलबाजार क्षेत्र में सोमवार को अतिक्रमण हटाने पहुंची ट्रैफिक पुलिस की टीम और स्थानीय व्यापारियों के बीच जमकर विवाद हो गया। कार्रवाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एडिशनल एसपी ट्रैफिक रामगोपाल करियारे और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक देखी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार, एएसपी करियारे अपनी टीम के साथ गोलबाजार और सदर बाजार में यातायात सुधार अभियान चला रहे थे। इस दौरान सड़क किनारे गलत ढंग से पार्क की गई गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। इसी बात पर एक व्यापारी ने आपत्ति जताई और एएसपी से बहस करते हुए तंज भरे लहज़े में कहा— सर, आपकी पढ़ाई को दाद देता हूं।

## एसईसीएल मे 41 वाँ स्थापना दिवस सोल्लासपूर्ण मनाया गया

# एसईसीएल एक बार फिर होगी देश की नंबर 1 कोयला कंपनी-हरीश दुहन

**बिलासपुर।** एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर में दिनांक 25.11.2025 को अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री हरीश दुहन, स्वतंत्र निदेशक श्री श्याम अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक श्री गजानंद देवराव असोले, निदेशक (तकनीकीङ्कसंचालन) श्री एन. फ्रैंकलिन जयकुमार, निदेशक (एचआर) श्री बिरंची दास, निदेशक (वित्त) श्री डी. सुनील कुमार, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री हिमांशु जैन तथा निदेशक (तकनीकी योजना/परियोजना) श्री रमेश चंद्र महापात्र, पूर्व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री व्हीके सहगल, पूर्व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एमके थापर, पूर्व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एमपी दीक्षित, पूर्व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री एके सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री ओमप्रकाश, पूर्व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री बीआर रेड्डी, पूर्व निदेशक तकनीकी (संचालन) श्री एलके श्रीवास्तव, पूर्व निदेशक तकनीकी (संचालन) श्री पीके रायचौधरी, पूर्व निदेशक तकनीकी (संचालन) श्री आरपी ठाकुर, पूर्व निदेशक तकनीकी (संचालन) श्री मनोज प्रसाद, पूर्व निदेशक (वित्त) श्री एके कोमावार, पूर्व निदेशक (वित्त) श्री श्याम मुरारी चौधरी, पूर्व निदेशक (वित्त) श्री जी श्रीनिवासन, पूर्व निदेशक (कार्मिक) श्री केके श्रीवास्तव, पूर्व निदेशक (कार्मिक) श्री राधेश्याम सिंह, पूर्व निदेशक (कार्मिक) श्री अनिल कुमार सिंह, एसईसीएल संचालन समिति के श्री सुजीत कुमार सिंह (बीएमएस), श्री नाथूलाल पाण्डेय (एचएमएस), श्री अजय विश्वकर्मा (एटक), श्री गोपाल नारायण सिंह (एसईकेएमसी) श्री वीएम मनोहर (सीटू), श्री एके पाण्डेय (सीएमओएआई), एसईसीएल कल्याण बोर्ड के श्री महेंद्र पाल सिंह (बीएमएस), श्री राजेश शर्मा (एटक), श्री अमृत लाल विश्वकर्मा (सीटू), श्री पी. चन्द्रकांत (सीएमओएआई) एसईसीएल सुरक्षा समिति के श्री संजय सिंह (बीएमएस), श्री बी धर्माराव (एटक), श्री इंद्रदेव चौहान (सीटू), श्री जीएस प्रसाद (सीएमओएआई), सिस्टा-कौंसिल एवं ओबीसी एसोसिएशन के श्री आरपी खांडे महासचिव सिस्टा, श्री एआर सिदार अध्यक्ष सिस्टा, श्री ओपी नवरंग अध्यक्ष कौंसिल, श्री ए विश्वास महासचिव कौंसिल, श्री अनिरूद्ध कुमार चंद्रा अध्यक्ष ओबीसी कोल इम्प्लाईज एवं विभिन्न क्षेत्रों से आए अधिकारी-कर्मचारीगण, विभिन्न विभागाध्यक्षों व स्थानीय अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति में एसईसीएल का 41 वां स्थापना दिवस सोल्लास मनाया गया। मुख्यालय परिसर में नवनिर्मित औडीटोरिअम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में अपने संबोधन में कंपनी के मुखिया सीएमडी श्री हरीश दुहन ने कहा कि 1985 में स्थापना के बाद से एसईसीएल देश की ऊर्जा सुरक्षा का मजबूत आधार रहा है और आगे भी यह भूमिका और सशक्त होगी। एसईसीएल की विरासत रिकॉर्ड-ब्रेकिंग उपलब्धियों से भरी है और हमारा लक्ष्य है कि एसईसीएल को एक बार फिर देश की नंबर 1 कोयला कंपनी बनाया जाए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि एसईसीएल टीम हर चुनौती को पार करने में सक्षम है। हमारे लिए सुरक्षित खनन, सतत विकास और कोयलांचल परिवार का कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। एसईसीएल न केवल ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है, बल्कि हरित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक अग्रणी संस्था है । कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य अतिथि एवं समस्त मंचस्थ अतिथियों द्वारा दीप-प्रज्ज्वलन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहित विशिष्ट अतिथियों, एसईसीएल संचालन समिति, कल्याण समिति, सुरक्षा समिति, सिस्टा, कौंसिल एवं ओबीसी एसोसिएशन के पदाधिकारियों का शाल, श्रीफल व पुष्पहार से आत्मीय सम्मान किया गया।

# स्टेशन पुनर्विकास कार्य में महत्वपूर्ण प्रगति........

■ बिलासपुर स्टेशन का द्वितीय प्रवेश द्वार व बुकिंग काउंटर 27 नवम्बर से अस्थायी रूप से बंद



**बिलासपुर।** अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बिलासपुर रेलवे स्टेशन को लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से विश्वस्तरीय यात्री सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। यात्रियों को अधिक सुगम, सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने हेतु स्टेशन पुनर्विकास कार्य चरणबद्ध रूप से प्रगति पर है बिलासपुर मंडल रेल प्रशासन द्वारा सूचित किया जाता है कि स्टेशन पुनर्निर्माण एवं यात्री सुविधाओं के उन्नयन कार्यों को गति देने के उद्देश्य से बिलासपुर स्टेशन का द्वितीय प्रवेश द्वार एवं वहाँ स्थित बुकिंग काउंटर को दिनांक 27 नवम्बर 2025 से अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। पुनर्विकास कार्य के इस चरण में द्वितीय प्रवेश द्वार से स्टेशन को जोड़ने वाली फुट ओवरब्रिज में मॉडिफिकेशन का कार्य किया जाएगा, जिससे यात्रियों की आवाजाही को और बेहतर बनाया जा सके। इस अवधि के दौरान यात्रियों से अनुरोध है कि वे मुख्य प्रवेश द्वार सहित उपलब्ध वैकल्पिक प्रवेश द्वारों एवं अन्य बुकिंग काउंटरों का उपयोग करें तथा स्टेशन परिसर में लगाए गए दिशा-सूचक बोर्डों और रेलवे कर्मियों के मार्गदर्शन का पालन करें। रेल प्रशासन यात्रियों को होने वाली संभावित असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है एवं उनसे सहयोग की अपेक्षा करता है।

# जिला पंचायत में मनाया गया संविधान दिवस.......

**बिलासपुर।** 26 नवम्बर 2025 को भारत का संविधान 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत हुआ था। इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिसके तहत आज जिला पंचायत बिलासपुर के सभाकक्ष में अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, दामोदर कांत जिला पंचायत सदस्य, संदीप कुमार अग्रवाल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जे.आर.भगत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मस्तूरी, कुमार सिंह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिल्हा एवं जिला पंचायत के समस्त अधिकारी / कर्मचारियों की उपस्थिति में संविधान दिवस मनाया गया है। कार्यक्रम में राजेश सूर्यवंशी अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा संबोधन करते हुए अवगत कराया गया कि संविधान निर्माण से हमारे सामाज एवं राष्ट्र के विकास में प्रगति आयी तथा संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। जिसके तहत हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति रख सकते है। संदीप कुमार अग्रवाल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर द्वारा संविधान निर्माण के संबंध में बताया गया कि संविधान निर्माण के पूर्व डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा सभी देशो के संविधानों का अध्ययन कर 02 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयास के पश्चात् भारत का संविधान निर्माण किया गया। सभी उपस्थितजनों के द्वारा संविधान दिवस पर प्रस्तावना का शपथपूर्वक पाठन किया गया साथ ही संविधान में दिये गये मौलिक कर्तव्यों, अधिकारो एवं मूल्यों पर विस्तार से चर्चा की गयी।

# अखिल भारतीय रेलवे पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महिला टीम का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा........

■ टीम चैंपियनशिप में प्रथम रनर-अप

■ विजेता खिलाड़ियों ने महाप्रबंधक से भेंट कर प्राप्त की बधाई; महाप्रबंधक ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया



**बिलासपुर।** देहरादून (उत्तराखंड) में 20 से 24 नवम्बर 2025 तक नॉर्दर्न रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित 21वीं पुरुष एवं 15वीं महिला अखिल भारतीय रेलवे पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025-26 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे खेल संघ की महिला पावरलिफ्टिंग टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 46 अंक अर्जित किए तथा महिला टीम चैंपियनशिप में प्रथम रनर-अप का गौरव प्राप्त किया । टीम की खिलाड़ियों ने अपने-अपने भार वर्ग में उत्कृष्ट दक्षता और अदम्य जिजीविषा का परिचय देते हुए एक स्वर्ण, दो रजत एवं दो कांस्य पदक जीते । 57 किलोग्राम भार वर्ग में जे. रामलक्ष्मी ने कुल 485 किग्रा भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि इसी वर्ग में ममता राजक ने 450 किग्रा भार के साथ रजत पदक प्राप्त किया । 63 किलोग्राम भार वर्ग में संतोषी मांझी ने कुल 432.5 किग्रा भार उठाकर कांस्य पदक अर्जित किया। 84 किलोग्राम वर्ग में प्रीति ने 510 किग्रा भार के साथ रजत तथा जानवी जगदीश ने 507.5 किग्रा भार के साथ कांस्य पदक जीता । इन सभी शानदार उपलब्धियों ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का गौरव बढ़ाया है तथा टीम की सामूहिक मेहनत और प्रतिबद्धता को मजबूती से स्थापित किया है। आज दिनांक 26 नवम्बर 2025 को टीम की विजेता महिला खिलाड़ियों ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय पहुँचकर महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश से सौजन्य भेंट की। महाप्रबंधक ने सभी खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर हार्दिक बधाई दी तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ प्रेषित करते हुए कहा कि खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन रेलवे के लिए प्रेरणास्रोत है और वे भविष्य में भी इसी उत्साह एवं समर्पण के साथ नई ऊँचाइयाँ प्राप्त करेंगी । इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारीगण, रेलवे खेल संघ के पदाधिकारियों तथा साथी खिलाड़ियों ने भी टीम को इस उपलब्धि पर बधाई दी और उनके सफल भविष्य की शुभकामनाएँ दी।

# कार्रवाई में साढ़े 7 लाख का अवैध धान जब्त किए

**बिलासपुर।** 26 नवम्बर 2025 को जिला प्रशासन की अवैध धान संग्रहण एवं परिवहन के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला आज भी जारी रहा। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जांच टीम ने पांच स्थलों पर छापामार कार्रवाई कर 7.44 लाख रूपए के अवैध धान जब्त किये। इन सभी आरोपियों के विरूद्ध मण्डी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिला खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने बताया कि पांचो संस्थानों के कब्जे से 533 बोरी ( 240 क्विंटल) धान बरामद किया गया है। राजस्व विभाग के नेतृत्व में खाद्य एवं मण्डी विभाग के अधिकारियों से बनी टीम द्वारा छापे की कार्रवाई की गई। इनमें बिल्हा के रूपचंद किराना स्टोर्स से 113 बोरी ( 45 क्विंटल) धान, ग्राम बरतोरी के ओम ट्रेडर्स से 188 बोरी (75 क्विंटल), कोटा में गुप्ता ट्रेडर्स संस्थान से 110 बोरी (44 क्विंटल) धान, रतनपुर के गंगाराम की दुकान पर 77 बोरी धान (30 क्विंटल) तथा रानीगांव के दुर्गा ट्रेडर्स से 115 बोरी (46) क्विंटल अवैध रूप से भण्डारित किये गये धान जब्त किया गया है। इसे मिलाकर जिले में अब तक लगभग 20 लाख रूपए मूल्य के अवैध धान जब्त किए गए हैं। अवैध धान संग्रहण एवं परिवहन के विरूद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

### बिना हेलमेट एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध बिलासपुर पुलिस की सख्त कार्रवाई

बिलासपुर। दिनांक 22, 23 एवं 24 नवंबर को सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर बिलासपुर जिले में विशेष चेकिंग अभियान संचालित किया गया।अभियान के अंतर्गत जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पूर्व से चिह्नित स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर बिना हेलमेट चलने वाले दोपहिया चालकों तथा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई।चेकिंग के दौरान कुल 174 वाहन चालकों पर बिना हेलमेट वाहन चलाने पर चालानी कार्रवाई की गई।इसी प्रकार 46 प्रकरणों में धारा 185 एम.वी. एक्ट के तहत शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों पर वैधानिक कार्रवाई की गई।बिलासपुर पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि स्वयं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमेशा हेलमेट पहनें एवं नशे की अवस्था में वाहन बिल्कुल न चलाएँ। आपका सहयोग ही सुरक्षित यातायात व्यवस्था की कुंजी है।

# सिम्स करेगा ताप विद्युत परियोजना क्षेत्र के ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर बड़ा अध्ययन

■ कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव और रोग प्रचलन का होगा वैज्ञानिक आकलन

**बिलासपुर।** छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर द्वारा एनटीपीसी सीपत ताप विद्युत परियोजना के 5 किमी दायरे में रहने वाले ग्रामीणों की स्वास्थ्य स्थिति का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने हेतु एक महत्वपूर्ण महामारी विज्ञान (एपिडेमियोलॉजिकल) अध्ययन शुरू किया जा रहा है जिसकी कुल लागत 9 लाख रुपए है। यह शोध कार्यान्वयन आधारित अनुसंधान के रूप में किया जाएगा, जिसके निष्कर्ष ग्रामीणों के स्वास्थ्य, पर्यावरणीय सुरक्षा और नीतिगत सुधार के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। एनटीपीसी सीपत, बिलासपुर जिले का प्रमुख कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, जिसकी तीन इकाइयों में लगभग 2080 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है और प्रतिदिन लगभग 42,000 मीट्रिक टन कोयले का उपयोग होता है। कोयले का खनन, परिवहन, दहन तथा फ्लाई ऐश का निपटान—ये सभी प्रक्रियाएँ पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए संभावित रूप से जोखिमपूर्ण मानी जाती हैं। विशेष रूप से 10 माइक्रोमीटर से छोटे कण (क्क10) फेफड़ों, हृदय और रक्तप्रवाह पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (हृस्न॥स्-5) के अनुसार इस क्षेत्र में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एनीमिया, मलेरिया जैसी बीमारियाँ वयस्कों में अधिक पाई जाती हैं, जबकि बच्चों में कुपोषण, बौनापन और एनीमिया की स्थिति चिंताजनक है। यह क्षेत्र स्थानीय स्तर पर प्रचलित जूनोटिक रोगों की दृष्टि से भी संवेदनशील माना जाता है, जिनकी निगरानी कोविड-19 महामारी के बाद और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इस अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीणों की वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति का आकलन, क्षेत्र में प्रचलित स्थानिक रोगों की पहचान, सामाजिक-जनसांख्यिकीय कारकों का विश्लेषण, तथा प्राधिकरणों को शमन उपायों की वैज्ञानिक सिफारिश उपलब्ध कराना है। शोध के निष्कर्ष ग्रामीण समुदायों के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाएँ तैयार करने में उपयोगी होंगे।

### अधिष्ठाता, सिम्स बिलासपुर डॉ. रमणेश मूर्ति

सीपत ताप विद्युत परियोजना क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों को समझना हमारे लिए एक सामाजिक और वैज्ञानिक ज़िम्मेदारी है। यह अध्ययन ग्रामीण आबादी में छिपे स्वास्थ्य जोखिमों और पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुझे विश्वास है कि यह शोध नीति-निर्माताओं को ठोस हस्तक्षेपों हेतु विश्वसनीय आधार प्रदान करेगा।

### चिकित्सा अधीक्षक, सिम्स डॉ. लखन सिंह

सीपत क्षेत्र एक औद्योगिक ज़ोन है जहाँ पर्यावरणीय प्रदूषण और उससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। सिम्स का यह अध्ययन ग्रामीणों की वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति को उजागर करेगा और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने, रोगों की रोकथाम तथा शीघ्र हस्तक्षेप रणनीतियाँ बनाने में बेहद सहायक सिद्ध होगा।

### विभागाध्यक्ष, कम्युनिटी मेडिसिन — डॉ. हेमलता ठाकुर

यह शोध न केवल स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करेगा, बल्कि सामाजिक-जनसांख्यिकीय कारकों, पर्यावरणीय जोखिमों और स्थानिक रोगों के आपसी संबंध को भी वैज्ञानिक रूप से उजागर करेगा। प्राप्त डेटा ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार, बच्चों में पोषण संबंधी समस्याओं के समाधान और पर्यावरणीय शमन उपायों के लिए एक मजबूत आधार बनेगा

## हनुमानजी अपनी शक्ति क्यों भूल गए थे?

श्री सीता हरण के बाद हनुमानजी और श्रीराम का मिलन हुआ और हनुमानजी ने श्रीराम को सुग्रीव, जामवंत आदि वानरयूथों से मिलाया। फिर जब लंका जाने के लिए रामसेतु बनाया गया तो श्रीराम ने हनुमानजी को लंका जाने का आदेश दिया, परंतु हनुमानजी ने लंका जाने में अपनी असमर्थता जताई तब जामवंतजी ने हनुमानजी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई। परंतु सवाल यह है कि हनुमानजी अपनी शक्ति क्यों भूल गए थे? दरअसल, हनुमानजी को कई देवताओं ने विभिन्न प्रकार के वरदान और अस्त्र-शस्त्र दिए थे। इन वरदानों और अस्त्र-शस्त्र के कारण बचपन में हनुमानजी उधम मचाने लगे थे। खासकर वे ऋषियों के बगीचे में घुसकर फल, फूल खाते थे और बगीचा उजाड़ देते थे। वे तपस्यारत मुनियों को तंग करते थे। उनकी शरारतें बढ़ती गई तो मुनियों ने उनकी शिकायत उनके पिता केसरी से की। माता-पिता में खूब समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते, परंतु हनुमानजी शरारत करने से नहीं रुके तो एक दिन अंगिरा और भृगुवंश के ऋषियों ने कुपित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि वे अपने शक्तियों और बल को भूल जाएंगे परंतु उचित समय पर उन्हें उनकी शक्तियों को कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगी। फिर जब हनुमानजी को श्रीराम का कार्य करना था तो जामवंत जी का हनुमानजी के साथ लंबा संवाद होता है। इस संवाद में वे हनुमानजी के गुणों का बखान करते हैं और तब हनुमानजी को अपनी शक्तियों का आभास होने लगता है। अपनी शक्तियों का आभास होते ही हनुमानजी विराट रूप धारण करते हैं और समुद्र को पार करने के लिए उड़ जाते हैं।

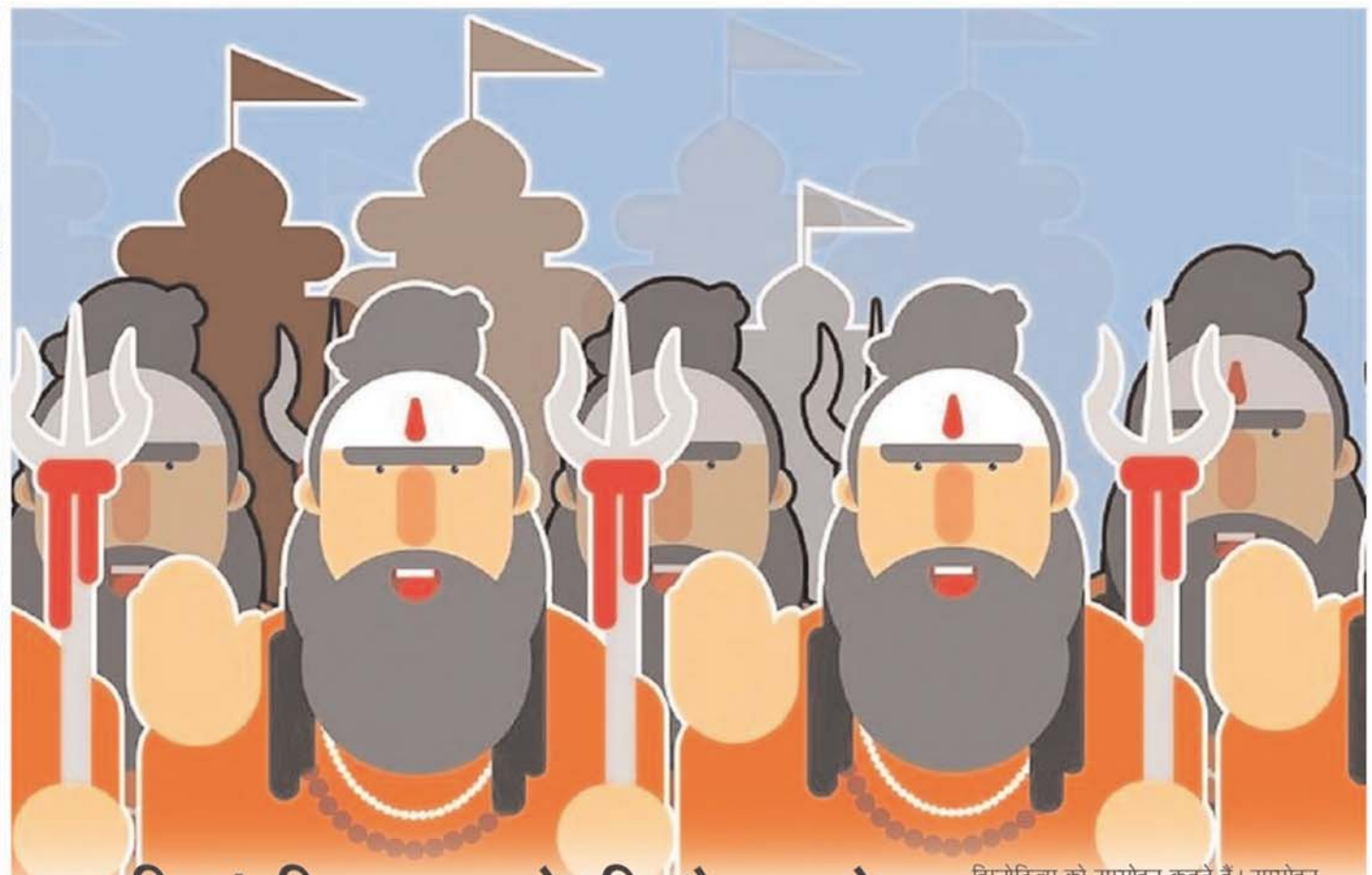

## छठी इंद्री क्या होती है, इसे कैसे जाग्रत किया जा सकता है

- छठी इंद्री को अंग्रेजी में सिक्स्थ सेंस कहते हैं। यह क्या होती है, कहां होती है और कैसे इसे जाग्रत किया जा सकता है यह जानना भी जरूरी है। इसे जाग्रत करने के लिए वेद, उपनिषद, योग आदि हिन्दू ग्रंथों में अनेक उपाय बताए गए हैं। नास्त्रेदमस इसी तरह के उपायों से भविष्यवक्ता बने थे।
- मस्तिष्क के भीतर कपाल के नीचे एक छिद्र है, उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वहीं से सुषुम्ना नाड़ी सहस्रकार के जुड़कर रीढ़ से होती हुई मूलाधार तक गई है। इसी नाड़ी के बायीं ओर इड़ा और दायीं ओर पिंगला नाड़ी स्थित है। दोनों के बीच सुप्तावस्था में छठी इंद्री स्थित है।
- यह छठी इंद्री ही हमें हर वक्त आने वाले खतरे या भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास करती रहती है लेकिन कुछ लोग इसे स्पष्ट समझ लेते हैं और कुछ नहीं। यदि आप इसे समझें तो आपके साथ घटने वाली घटनाओं के प्रति ये इंद्री आपको सजग कर देगी।
- छठी इंद्री जाग्रत होने से व्यक्ति में भूत और भविष्य में झांकने की क्षमता आ जाती है। ऐसा व्यक्ति मीलों दूर बैठे व्यक्ति की बातें सुन सकता और उसे देख भी सकता है। दूसरों के मन की बात जान ही नहीं सकता बल्की उनका मन बदल भी सकता है और दूसरों की बीमारी दूर की जा सकती है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार छठी इंद्री कल्पना नहीं, वास्तविकता है, जो हमें किसी घटित होने वाली घटना का पूर्वाभास कराती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के रॉन रेसिक के अनुसार छठी इंद्रिय के कारण ही हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है।
- छठी इंद्री को जाग्रत करने का बहुत ही सरल तरीका है। तीन माह के लिए खुद को परिवार और दुनिया से काटकर आपको योग की शरण में जाना होगा। यम, नियम, प्राणायाम और योगासन करते हुए लगातार ध्यान करना होगा।
- प्राणायाम सबसे उत्तम उपाय इसलिए माना जाता है क्योंकि हमारी दोनों भौहों के बीच छठी इंद्री होती है। सुषुम्ना नाड़ी के जाग्रत होने से ही छठी इंद्री जाग्रत हो जाती है। प्राणायम के माध्यम से छठी इंद्री को जाग्रत किया जा सकता है।
- मेस्मेरिज्म या हिप्नोटिज्म जैसी अनेक विद्याएं इस छठी इंद्री को जाग्रत करने का सरल और शॉर्टकट रास्ता है लेकिन इसके खतरे भी हैं। हिप्नोटिज्म को सम्मोहन कहते हैं। सम्मोहन विद्या को ही प्राचीन समय से 'प्राण विद्या' या 'त्रिकालविद्या' के नाम से पुकारा जाता रहा है।
- मन के कई स्तर होते हैं। उनमें से एक है सुक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ आदिम आत्म चेतन मन। यह मन हमें आने वाले रोग या खतरें का संकेत देकर उससे बचने के तरीके भी बताता है। इस मन को प्राणायाम या सम्मोहन से साधा जा सकता है।
- त्राटक क्रिया से भी इस छठी इंद्री को जाग्रत कर सकते हैं। आप बिना पलक गिराए किसी एक बिंदु, क्रिस्टल बॉल, मोमबत्ती या घी के दीपक की ज्योति पर देखते रहिए। इसके बाद आंखें बंद कर ध्यान करें। कुछ समय तक इसका अभ्यास करें। इससे धीरे-धीरे छठी इंद्री जाग्रत होने लगेगी।
- ऐसा कई बार देखा गया है कि कई लोगों ने अंतिम समय में अपनी बस, ट्रेन अथवा हवाई यात्रा को कैंसिल कर दिया और वे चमत्कारिक रूप से किसी दुर्घटना का शिकार होने से बच गए। बस यही छठी इंद्री का कमाल है। आप इसे पहचानें क्योंकि यह सभी संवेदनशील लोगों के भीतर होती है।
- यदि आपको यह आभास होता है कि पीछे कोई चल रहा है या दरवाजे पर कोई खड़ा है। कुछ होनी-अनहोनी होने वाली है या कोई खुशी का समाचार मिलने वाला है तो आप अपनी इस क्षमता पर लगातार गौर करें और ध्यान देंगे तो यह विकसित होने लगेगी। जैसे-जैसे अभ्यास गहराएगा आपकी छठी इंद्री जाग्रत होने लगेगी और आप भविष्यवक्ता बन जाएंगे।

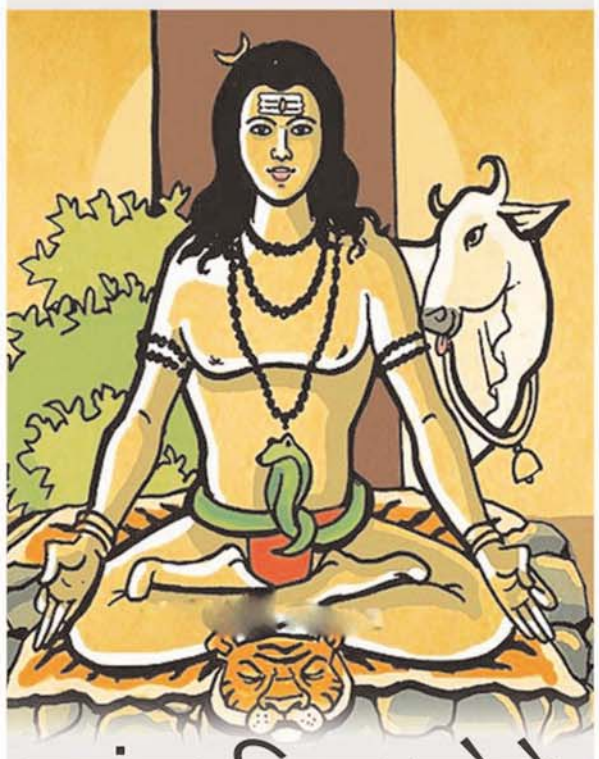

## तुरंत सिद्ध होते हैं साबर मंत्र

**वैदिक अथवा तांत्रोक्त अनेक ऐसे मंत्र हैं, जिसमें साधना करने के लिए अत्यंत सावधानी की जरूरत होती है। असावधानी से कार्य करने पर प्रभाव प्राप्त नहीं होता अथवा सारा श्रम व्यर्थ चला जाता है, परंतु शाबर मंत्रों की साधना या सिद्धि में ऐसी कोई आशंका नहीं होती। यह सही है कि इनकी भाषा सरल और सामान्य होती है।**

माना जाता है कि लगभग सभी साबर साधनाओं और मंत्रों का अविष्कार गुरु गोरखनाथ ने किया है। यह मंत्र बहुत जल्दी ही सिद्ध भी हो जाते हैं और इनकी साधनाएं बहुत ही सरल होती हैं। ओम गुरुजी को आदेश गुरजी को प्रणाम, धरती माता धरती पिता, धरती धरे ना धीरबाजे श्रींगी बाजे तुरतुरि आया गोरखनाथमीन का पुत मुंज का छड़ा लोहे का कड़ा हमारी पीठ पीछे यति हनुमंत खड़ा, शब्द सांचा पिंड काचास्फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा।।

इस मन्त्र को सात बार पढ़ कर चाकू से अपने चारों तरफ रक्षा रेखा खींच ले गोलाकार, स्वयं हनुमानजी साधक की रक्षा करते हैं। शर्त यह है कि मंत्र को विधि विधान से पढ़ा गया हो।

साबर मंत्रों को पढ़ने पर ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं होता कि इनमें कुछ विशेष प्रभाव है, परंतु मंत्रों का जप किया जाता है तो असाधारण सफलता दृष्टिगोचर होती है। कुछ मंत्र तो ऐसे हैं कि जिनको सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, केवल कुछ समय उच्चारण करने से ही उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यदि किसी मंत्र की संख्या निर्धारित नहीं है तो मात्र 1008 बार मंत्र जप करने से उस मंत्र को सिद्ध समझना चाहिए। दूसरी बात शाबर मंत्रों की सिद्धि के लिए मन में दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। जिस प्रकार की इच्छा शक्ति साधक के मन में होती है, उसी प्रकार का लाभ उसे मिल जाता है। यदि मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो अन्य किसी भी बाह्य परिस्थितियों एवं कुविचारों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता।

## 9 प्रमुख मणियां किस मणि को धारण करने से क्या होता है

आपने पारस मणि, नागमणि, कौस्तुभ मणि, चंद्रकांता मणि, नीलमणि, स्यमंतक मणि, स्फटिक मणि आदि का नाम तो सुना ही होगा, परंतु ही यहां निम्नलिखित नौ मणियों की बात कर रहे हैं- घृत मणि, तैल मणि, भीष्मक मणि, उपलक मणि, स्फटिक मणि, पारस मणि, उलूक मणि, लाजावर्त मणि, मासर मणि। आओ जानते हैं कि इन मणियों को धारण करने से क्या होता है। हालांकि यह सभी बातें मान्यता पर आधारित हैं।

- घृत मणि की माला धारण कराने से बच्चों को नजर से बचाया जा सकता है।
- स्फटिक मणि को धारण करने से कभी भी लक्ष्मी नहीं रूठती।
- तैल मणि को धारण करने से बल-पौरूष की वृद्धि होती है।
- भीष्मक मणि धन-धान्य वृद्धि में सहायक है।
- उपलक मणि को धारण करने वाला व्यक्ति भक्ति व योग को प्राप्त करता है।
- उलूक मणि को धारण करने से नेत्र रोग दूर हो जाते हैं।
- लाजावर्त मणि को धारण करने से बुद्धि में वृद्धि होती है।
- मासर मणि को धारण करने से पानी और अग्नि का प्रभाव कम होता है।

## तेलमणि को धारण करने से होती हैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण

आपने पारस मणि, नागमणि, कौस्तुभ मणि, चंद्रकांता मणि, नीलमणि, स्यमंतक मणि, स्फटिक मणि आदि का नाम तो सुना ही होगा, परंतु ही यहां निम्नलिखित नौ मणियों की बात कर रहे हैं- घृत मणि, तैल मणि, भीष्मक मणि, उपलक मणि, स्फटिक मणि, पारस मणि, उलूक मणि, लाजावर्त मणि, मासर मणि। आओ जानते हैं कि तेलमणि को धारण करने से क्या होता है। हालांकि यह सभी बातें मान्यता पर आधारित हैं।

- तेलमणि को उदउक, उदोक भी कहते हैं और अंग्रेजी में टूर्मेलीन कहा जाता है।
- लाल रंग की आभा लिए हुए श्वेत, पीत व कृष्ण वर्ण की होती है तेलमणि और स्पर्श करने से तेल जैसा चिकना ज्ञात होता है।
- कहते हैं कि श्वेत रंग की तेलमणि को अग्नि में डालने पर ही पीत वर्ण की तथा कपड़े में लपेट कर रखने पर तीसरे दिन पीत वर्ण की हो जाती है। लेकिन बाहर निकालकर हवा में रखने से कुछ समय बाद ही यह पुनः अपने असली रंग में बदल जाती है।
- इस मणि को धारण करने से भक्ति भाव, वैराग्य तथा आत्म ज्ञान प्राप्त होकर सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
- कहते हैं कि रोहिणी नक्षत्र, पूर्णिमा या मंगलवार के दिन तेलमणि को जिस खेत में 4-5 हाथ गहरे गड्ढे में खोदकर दबा दिया जाए और मिट्टी से ढंककर सींचा जाए तो सामान्य से बहुत अधिक अन्न उत्पन्न होता है।

## इन कारणों से दिखाई देते हैं हमें अच्छे या बुरे सपने

**मनोविज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष और योग में अच्छे या बुरे सपने दिखाई देने के कई कारण बताए गए हैं। जब हम कोई स्वप्न देखते हैं तो जरूरी नहीं कि प्रत्येक सपने का अच्छा या बुरा फल होता है। आओ जानते हैं कि सपने किन कारणों से दिखाई देते हैं।**

अधिकतर सपने हमें हमारी दिनचर्या में किए गए कार्य से प्राप्त होते हैं। कार्य का अर्थ हमने जो देखा, सुनना, समझा, इच्छा किया और भोगा वह हमारे चित्त में विराजित होकर रात में स्वप्नों के रूप में दिखाई देता है। यह सब बदले स्वरूप में इसलिए भी होते हैं क्योंकि वे हमारे शरीर में स्थित भोजन और पानी की स्थिति और अवस्था से भी संचालित होते हैं। निम्नलिखित बातों से आप समझ सकते हैं। इन कारणों से दिखाई देते हैं स्वप्न :-

- दृष्ट- जो जाग्रत अवस्था में देखा गया हो उसे स्वप्न में देखना।
- श्रुत- सोने से पूर्व सुनी गई बातों को स्वप्न में देखना।
- अनुभूत- जो जागते हुए अनुभव किया हो उसे देखना।
- प्रार्थित- जाग्रत अवस्था में की गई प्रार्थना की इच्छा को स्वप्न में देखना।
- दोषजन्य- वात, पित्त आदि दूषित होने से स्वप्न देखना।
- भाविक- जो भविष्य में घटित होना है, उसे देखना।

अतः अब आप जान सकते हैं कि आपने जो सपने देंखे हैं वे किस श्रेणी के हैं। इससे आप यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि आपका सपना शुभ होगा या अशुभ।

## हिन्दू धर्म में सफेद वस्त्र का क्या है महत्व

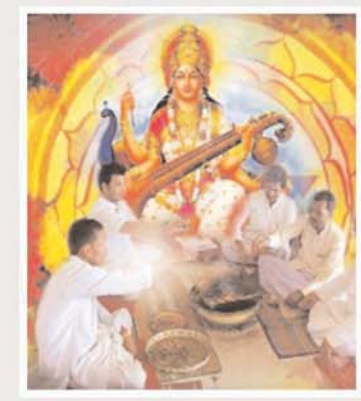

**हिन्दू धर्म में सफेद वस्त्र का बहुत महत्व है। सफेद रंग हर तरह से शुभ माना गया है, लेकिन वक्त के साथ लोगों ने इस रंग का मांगलिक कार्यों में इस्तेमाल बंद कर दिया। हालांकि प्राचीनकाल में सभी तरह के मांगलिक कार्यों में इस रंग के वस्त्रों का उपयोग किया जाता था। यह रंग शांति, शुभता, पवित्रता और मोक्ष का रंग है।**

**लक्ष्मी का वस्त्र** : सच तो यह है कि सफेद रंग सभी रंगों में अधिक शुभ माना गया है इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्मी हमेशा सफेद कपड़ों में निवास करती है।

**मांगलिक वस्त्र** : 20-25 वर्षों पहले तक लाल जोड़े में सजी दुल्हन को सफेद ओढ़नी ओढ़ाई जाती थी। इसका यह मतलब कि दुल्हन ससुराल में पहला कदम रखे तो उसके सफेद वस्त्रों में लक्ष्मी का वास हो। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में सफेद ओढ़नी की परंपरा का पालन किया जाता है।

**यज्ञकर्ता का वस्त्र** : प्राचीन काल में जब भी यज्ञ किया जाता था तो पुरुष और महिला दोनों ही सफेद वस्त्र ही धारण करके बैठते थे। पुरोहित वर्ग इसी तरह के वस्त्र पहनकर यज्ञ करते थे। दूसरी ओर आज भी किसी भी सम्मान समारोह आदि में सफेद कुर्ता और धोती पहनने का रिवाज है।

**विधावा का वस्त्र** : यदि किसी का पति मर गया तो उसे विधवा और किसी की पत्नी मर गई है तो उसे विधुर कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार पति की मृत्यु के नौवें दिन उसे दुनियाभर के रंगों को त्यागकर सफेद साड़ी पहननी होती है, वह किसी भी प्रकार के आभूषण एवं श्रृंगार नहीं कर सकती। स्त्री को उसके पति के निधन के कुछ सालों बाद तक केवल सफेद वस्त्र ही पहनने होते हैं और उसके बाद यदि वह रंग बदलना चाहे तो बेहद हल्के रंग के वस्त्र पहन सकती है। मध्यकाल में हिन्दू धर्म में कई तरह की बुराइयां सम्मलित हुई उसमें एक यह भी थी कि कोई स्त्री यदि विधवा हो जाती थी तो वह दूसरा विवाह नहीं कर पाती थी। हालांकि आज भी उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में विधवा विवाह का प्रचलन है जिसे नाता कहा जाता है। कोई स्त्री पुनर्विवाह का निर्णय लेती है, तो इसके लिए वह स्त्रतंत्र है। आज समाज का स्वरूप बदल रहा है। विधवाएं रंगीन वस्त्र भी पहन रही है और शादी भी कर रही हैं। वेदों में एक विधवा को सभी अधिकार देने एवं दूसरा विवाह करने का अधिकार भी दिया गया है। वेदों में एक कथन शामिल है-

*'उदीरष्व नार्यभि जीवलोकं*
*गतासुमेतमुप शेष एहि।*
*हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं*
*पत्युर्जनित्वमभि सम्बभूथ।'*

अर्थात पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा उसकी याद में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दे, ऐसा कोई धर्म नहीं कहता। उस स्त्री को पूरा अधिकार है कि वह आगे बढ़कर किसी अन्य पुरुष से विवाह करके अपना जीवन सफल बनाए। चार कारणों से विधवा महिलाओं को सफेद वस्त्र दिए गए। पहला यह कि यह रंग कोई रंग नहीं बल्कि रंगों के अनुपस्थिति है। मतलब यह कि अब जीवन में कोई रंग नहीं बचा। दूसरा यह कि इससे महिला की एक अलग पहचान बन जाती है और लोग उसे सहानुभूति एवं संवेदना रखते हैं। तीसरा यह कि सफेद रंग आत्मविश्वास, सात्विक और शांति का रंग है। इसके साथ ही सफेद वस्त्र विधवा स्त्री को प्रभु में अपना ध्यान लगाने में मदद करते हैं। चौथा कराण यह कि इससे महिला का कहीं ध्यान नहीं भटकता है और उसे हर वक्त इसका अहसास होता है कि वह पवित्र है। पांचवां कारण यह कि यदि महिला के कोई पुत्र या पुत्री है तो वह अपने भीतर नैतिकता और जिम्मेदारी का अहसास करती रहे ताकि वह दूसरा विवाह नहीं करें। दोबारा शादी नहीं करने से पुत्र पुत्रियों के जीवन पर विपरित या प्रतिकुल असर नहीं पड़ता है।

# संविधान दिवस पर जिला न्यायालय में न्यायाधीशगण, अधिवक्ताओं एवं अभियोजन अधिकारियों की संयुक्त कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन

**दुर्ग।** दिनांक 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग के नवीन सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण तथा अभियोजन अधिकारियों की संयुक्त कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में न्यायिक प्रक्रिया की गुणवत्ता, संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण और न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाने पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। उक्त कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

कार्यक्रम के प्रारंभ में तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने कहा कि संविधान दिवस केवल एक औपचारिक अवसर नहीं, बल्कि न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में मूलभूत नैतिक संकल्पों का पुन:स्मरण है। उन्होंने जोर दिया कि प्रत्येक अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी और अभियोजन अधिकारी को संविधान की मंशा को समझते हुए कार्य करना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक के उपयोग, पारदर्शिता और समयबद्धता न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। न्यायालय में आचार-व्यवहार, वकालत की गरिमा, और विधि के प्रति समर्पण संवैधानिक नैतिकता का अनिवार्य हिस्सा है।

इसके पश्चात जिला अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष सुश्री नीता जैन ने अपने संबोधन में कहा कि अधिवक्ता संविधान के संरक्षकों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि युवा अधिवक्ताओं को संविधान के सिद्धांतों की गहराई से समझ विकसित करनी चाहिए तथा पेशे की गरिमा बनाए रखते हुए वकालत के माध्यम से समाज में न्यायपूर्ण वातावरण स्थापित करना चाहिए। उन्होंने न्यायपालिका और अधिवक्ताओं के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को न्यायिक व्यवस्था की मजबूती का आधार बताया।

इसके पश्चात प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि भारत का संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों पर आधारित एक जीवंत दस्तावेज है, जो न्यायपालिका, अधिवक्ताओं और अभियोजन अधिकारियों को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया तभी सार्थक होती है जब सभी संवैधानिक सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से लागू किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को त्वरित एवं प्रभावी न्याय मिले। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय, अधिवक्ता संघ और अभियोजन इन तीनों संस्थाओं के बीच समन्वय एवं सहयोग से ही न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, कुशल और संवेदनशील बनाया जा सकता है।

उक्त कार्यक्रम में संविधान दिवस के महत्व को चित्रित करती हुई रंगोली बनाई गई थी तथा उक्त कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वॉलेंटियर एवं केंद्रीय जेल दुर्ग के बंदियों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स का भी प्रदर्शन किया गया।

कार्यशाला का समापन संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक वाचन एवं संवैधानिक मूल्यों के पालन के संकल्प के साथ हुआ। कार्यक्रम में न्यायाधीशगण, जिला अधिवक्ता संघ तथा लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्तागण, अभियोजन अधिकारीगण, जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के अधिकारी-कर्मचारी तथा पैरालीगल वालेंटियर उपस्थित रहे।

# संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ

**दुर्ग।** आज संविधान दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा एक गरिमामय एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित स्थायी एवं जनोपयोगी लोक अदालत के अध्यक्ष, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिवक्ताओं, कर्मचारियों एवं पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत संविधान निर्माता महापुरुषों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की गई। स्थायी एवं जनोपयोगी लोक अदालत के अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में कहा कि - संविधान की प्रस्तावना हमारे राष्ट्र के लोकतांत्रिक चरित्र, मूल अधिकारों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों का मार्गदर्शक आधार है। प्रत्येक नागरिक तथा न्याय से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसका निष्ठापूर्वक पालन सर्वोपरि कर्तव्य है।

अध्यक्ष ने यह भी कहा कि प्रस्तावना का दैनिक जीवन में अनुपालन ही सच्चे अर्थों में संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य है। इसी भावना के साथ सभी उपस्थित प्रतिभागियों ने गौरव एवं उत्साह के साथ प्रस्तावना का पठान किया। कार्यक्रम में उपस्थित लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिवक्ताओं, कर्मचारियों एवं पैरालीगल वालेंटियर्स ने इस पहल की सराहना करते हुए संविधान के मूल्यों के संरक्षण एवं प्रसार के लिए निरंतर योगदान देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अंत में स्थायी एवं जनोपयोगी लोक अदालत के अध्यक्ष ने सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि संविधान दिवस हमें हर वर्ष अपने लोकतांत्रिक दायित्वों और संवैधानिक आदर्शों को याद करने और उन्हें जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है।

# मतदाताओं के बीच फोटो संबंधी भ्रांतियों को दूर करने बीएलओ करें घर-घर जागरूकता

## बूथ लेवल अधिकारी भी सीधे बीएलओ एप के माध्यम से फोटो खींचकर अपलोड कर सकते है

**गरियाबंद।** पुनरीक्षण (एसआईआर) अर्हता तिथि 01.01.2026 के संदर्भ में पुनरीक्षण का कार्य आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपादित कराया जा रहा हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को पत्र प्रेषित कर कहा है कि आयोग के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार बूथ लेवल अधिकारी 4 दिसम्बर 2025 तक घर-घर जाकर मतदाताओं से विधिवत् भरा हुआ गणना पत्रक (इन्युमिरेशन फार्म) प्राप्त करेंगे। बूथ लेवल अधिकारी द्वारा वितरित गणना पत्रक में यदि मतदाता अपने फोटो से संतुष्ट नहीं हैं या फोटो धुंधला है अथवा अस्पष्ट हैं, ऐसी स्थिति में मतदाता चाहे तो अपना नवीन फोटो उपलब्ध होने पर बूथ लेवल अधिकारी को उपलब्ध करा सकेंगे। बूथ लेवल अधिकारी भी सीधे बीएलओ एप के माध्यम से फोटो खींचकर अपलोड कर सकते है। सभी मतदाताओं को फेटो देने की आवश्यकता नहीं हैं। मतदाताओं को अनिवार्यतः नवीन फोटो उपलब्ध कराने संबंधी मतदाताओं के मध्य फैल रही भ्रांतियों के संबंध में अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक किया जायें। उक्त निर्देशों को बीएलओ सुपरवाइजर के संज्ञान में अवश्य लायें साथ ही विधानसभा स्तर पर सभी राजनैतिक दलों की बैठक आहूत कर वस्तुस्थिति से अवगत करावें।

# ग्रामीण स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में मोपकी के टीम विजयी घोषित

**बलौदाबाजार।** जय बूढ़ा देव क्रिकेट समिति एवं ग्राम पंचायत ढाबाडीह के संयुक्त तत्वाधान में भव्य ग्रामीण स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया द्य यह आयोजन में कुल 32 टीमों ने भाग लेकर अपने खेल का प्रदर्शन कर खेल भावना का परिचय दिया । यह आयोजन दिनांक 15 नवंबर से शुभारंभ होकर 23 नवंबर को समापन हुआ। फाइनल मैच मौपकी एवं मोपका टीम के बीच सम्पन्न हुआ द्य जिससे मोपकी के टीम विजयी घोषित हुआ द्य द्वितीय स्थान पर मोपका, तृतीय भोथी डीह, एवं चतुर्थ स्थान पर केश डबरी रहे द्य समापन एवं पुरस्कार वितरण में राष्ट्रीय पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण मंच छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष के के वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता हेमंत ध्रुव सरपंच ढाबाडीह ने किया । मुख्य अतिथि के के वर्मा ने ग्राम वासी एवं खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेल के क्षेत्र में अपार संभावनाये हैं, खिलाड़ियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत एवं लगन के साथ खेल भावना एवं अनुशासन में रहते हुए अपने खेल का प्रदर्शन करते रहना चाहिए द्य मुख्य अतिथि श्री वर्मा ने युवाओं एवं ग्रामीणों को नशे से दूर रहने की अपील की द्य कार्यक्रम को सरपंच हेमंत ध्रुव ने भी संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में इससे बेहतर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। समापन समारोह में प्रथम 21000, एवं ट्रॉफी, द्वितीय 11000 एवं ट्रॉफी, तृतीय 5000 एवं ट्रॉफी, चतुर्थ 3000 एवं ट्रॉफी के साथ मैंन ऑफ द मैच,बेस्ट बैट्समैन,बेस्ट कीपर,बेस्ट फिल्डर, के अलावा बेस्ट ऑलराउंडर खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया द्य इस अवसर पर भुनेश्वर ध्रुव, डीवेंडर वर्मा,दीपक ध्रुव,योगी वर्मा, गोपाल दास,अमित निर्मलकर,महादेव ध्रुव जितेंद्र फ़ेक्कर के अलावा भारी संख्या मे ग्रामीण एवं खिलाड़ी उपस्थित थे । कार्यक्रम का संचालन ओमप्रकाश वर्मा ने किया जबकि आभार व्यक्त क्षेत्रीय जनपद सदस्य चंद्रशेखर ध्रुव ने किया द्य उक्त जानकारी सीनियर खिलाड़ी एवं सरपंच हेमंत ध्रुव ने दी ।

# संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन एवं स्वदेशी मध्यस्थता विषय पर संगोष्ठी

**दुर्ग।** संविधान दिवस के अवसर पर आज, 26 नवम्बर 2025 को मध्यस्थता केन्द्र, जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मध्यस्थता प्रभारी अधिकारी के नेतृत्व में मध्यस्थ अधिवक्ताओं, जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग के अधिवक्तागण, पक्षकारों एवं कर्मचारियों ने एकजुट होकर संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया।

कार्यक्रम की शुरुआत में मध्यस्थता प्रभारी अधिकारी ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की अहमियत को रेखांकित करते हुए, संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वदेशी मध्यस्थता प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से मध्यस्थता की प्रथा प्रचलित रही है, और वर्तमान समय में विवादों के त्वरित निपटारे के लिए स्वदेशी मध्यस्थता प्रणाली सबसे प्रभावी समाधान साबित हो सकती है। उन्होंने इसके माध्यम से विवादों को कम खर्च में और शीघ्र निपटाने का आग्रह किया।

कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ मध्यस्थ श्री अशोक जायसवाल ने अपने प्रेरक वक्तव्य में भारतीय प्राचीन इतिहास में मध्यस्थता (Mediation) की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि भारत में विवादों के शांतिपूर्ण निपटान की परंपरा सदियों पुरानी है। प्राचीन काल में ग्राम पंचायत, कुल परिषद, श्रेणी संगठनों तथा जनपद सभाओं के माध्यम से विवादों का समाधान संवाद, आपसी सहमति एवं परस्पर सम्मान के आधार पर किया जाता था। मध्यस्थता केवल एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और भारतीय समाज की उदात्त परंपरा का सशक्त अंग है। आज इसे पुन: अपनाना न केवल न्यायिक भार को कम करेगा, बल्कि समाज में सौहार्द और सहयोग की भावना को भी मजबूत करेगा।

इसके अतिरिक्त, श्री ढाल सिंह देवागंन, अधिवक्ता मध्यस्थ ने भी मध्यस्थता को विवादों के समाधान का एक आसान और प्रभावी तरीका बताया, जिससे दो पक्षों के बीच सुलह-सफाई कर समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सकता है। श्रीमती कविता गिरी गोस्वामी, अधिवक्ता मध्यस्थ ने कहा कि मध्यस्थता केवल कानूनी विवादों का समाधान नहीं करती, बल्कि यह दो पक्षों के बीच आपसी रिश्तों को सुधारने और प्रेम व सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करने का भी एक जरिया है।

कार्यक्रम का समापन मध्यस्थता के महत्व को समझाते हुए स्वदेशी मध्यस्थता प्रणाली को बढ़ावा देने के साथ किया गया।

# पुलिसिया कार्रवाई: गोंदिया से धमतरी जा रहा ट्रक पकड़ाया, ढाई सौ क्विंटल धान जब्त

## एमएमसी जिला पुलिस ने अवैध परिवहन पर कार्रवाई की, खाद्य विभाग को सौंपा मामला

**राजनांदगांव।** धान खरीदी शुरू होते ही उसका अवैध परिवहन भी शुरू हो गया है। ऐसा ही एक मामला मोहला-मानपुर-चौकी जिले में सामने आया है, जहां ट्रक से तकरीबन ढाई सौ क्विंटल धान गोंदिया महाराष्ट्र से धमतरी ले जाया जा रहा था। सूचना के आधार पर चिल्हाटी पुलिस ने कार्रवाई की और पूरे प्रकरण को खाद्य विभाग को सौंप दिया। आगे इस मामले की जांच और कार्रवाई विभागीय अमला करेगा। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को खबर मिली कि महाराष्ट्र की ओर से ट्रक में लोडकर धान को छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है। इस पर पुलिस ने वाहनों की जांच करना शुरू किया। इस पर चिल्हाटी पुलिस चौकी एरिया में ट्रक एमएच 29 एएन 3786 को रोका गया। उसमें 290 कट्टा धान लोड था, जिसका वजन तकरीबन 259 क्विंटल बताया गया था। चालक से जानकारी लेने पर वह कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। इस पर खाद्य विभागी की टीम को बुलाया गया। उन्होंने भी मौके पर जांच की और मामला अवैध परिवहन का सामने आया। जिला पुलिस की टीम ने मामले को खाद्य विभाग को सौंप दिया है। आने वाले दिनों में जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि धान को अवैध रूप से किस संस्थान से कहां ले जाया जा रहा था। ज्ञात हो कि धान की आवक अवैध रूप से होने की आशंका को देखते हुए राजनांदगांव, मोहला-मानपुर और खैरागढ़ जिले के बार्डर वाले हिस्सों में लगातार चेकिंग की जा रही है। इसमें बड़ी मात्रा में धान जब्त किया जा रहा है।

## कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक

# खरीदी केंद्रों में किसानों को मिले बेहतर सुविधाएँ: राजेंद्र कटारा

**बलरामपुर।** कलेक्टर राजेन्द्र कटारा ने समय-सीमा की बैठक में चल रही धान खरीदी व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करते हुए जिले के उपार्जन केंद्रों में किसानों की दैनिक आवक,तुलाई की प्रगति,परिवहन व्यवस्था,बारदाना उपलब्धता तथा स्टॉक प्रबंधन की स्थिति की अद्यतन जानकारी ली और कहा कि सभी समितियों में धान खरीदी का कार्य सुचारु रूप से करें ताकि खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने धान खरीदी से संबंधित सभी अधिकारियों को प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और राइस मिलों का भौतिक सत्यापन कर किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में वनमण्डलाधिकारी आलोक वाजपेयी,जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर,अपर कलेक्टर अभिषेक गुप्ता,चेतन बोरघरिया, प्रमोद गुप्ता,सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

**ध्वनि प्रदूषण पर करें सख्त कार्रवाई-**कलेक्टर ने कहा कि बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है,अतः सामाजिक कार्यक्रमों में उपयोग होने वाले साउंड सिस्टम से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। इसके लिए सभी साउंड सिस्टम संचालकों की बैठक लेकर संज्ञान में लाए साथ ही निर्देशों का पालन नहीं करने पर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

**आवारा कुत्तों से लोगों की करें रक्षा-**उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की विकासखंडवार समीक्षा कर निर्माणाधीन एवं पूर्ण आवासों की स्थिति का जानकारी ली तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने रबी फसल हेतु खाद-बीज वितरण की स्थिति, पेयजल आपूर्ति की प्रगति एवं स्वीकृत निर्माण कार्यों की अद्यतन प्रगति की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने पशुपालन विभाग अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट,आवारा पशु नियंत्रण तथा अन्य गतिविधियों की समीक्षा की। साथ ही शहरी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की समस्या पर भी विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

**तातापानी महोत्सव के लिए हो जाए सज्ज-**कलेक्टर ने आगामी तातापानी महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा कर कहा कि तातापानी महोत्सव जिले का प्रमुख आयोजन है,इस लिए संबंधित विभागों को सौंपे गए दायित्वों का समय-सीमा में पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही महोत्सव को भव्य एवं सफल बनाने के लिए सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य करना सुनिश्चित करें।

**प्राप्त आवेदनों का समय पर करें निराकरण-**जनदर्शन में आमजनों से प्राप्त शिकायत एवं समस्याओं को प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्रेषित करते हुए समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए गए। गंभीरता पूर्वक सुन सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बीएलओ को प्रशस्ति पत्र से किया सम्मानित-उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन बीएलओ एवं तीन अविहित अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। सामरी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र 142, गजाधरपुर (क) की बीएलओ कंचन पैकरा एवं अविहित अधिकारी सुषमा तथा मतदान केन्द्र 141, गजाधरपुर की बीएलओ भोजपती पैकरा एवं अविहित अधिकारी सुमन भगत पैकरा को गणना पत्रकों के डिजिटाइजेशन कार्य को प्रभावी ढंग से पूर्ण करने पर सम्मानित किया। इसी प्रकार रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र 245, तरकाखाड़ की बीएलओ शांति यादव एवं अविहित अधिकारी संजय कुमार मिंज को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र कटारा ने सभी सम्मानित अधिकारी-कर्मचारी को बधाई दी तथा अन्य बीएलओ को भी तत्परता एवं गुणवत्ता के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।

# पार्षद ने जमा किया एसआईआर गणना पत्र

**रामानुजगंज।** नगर पालिका परिषद रामानुजगंज के पार्षद विकास गुप्ता ने अपना एवं अपने परिवार का एसआईआर गणना पत्र बीएलओ को सौंपा। और कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे विशेष ग्रहण पुनरीक्षण के पत्र को भरकर सभी लोगों को अपने-अपने बीएलओ को सौंपना है। इस बात का सभी को ध्यान में रखना होगा कि निर्धारित समय अवधि में सभी अपने फार्म जमा कर दें।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजय तिवारी द्वारा असमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रास मेमोरियल सेंटर के बाजू, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित करवाकर व गदा चौक, फरीद नगर रोड स्वर्गीय तुलाराम मेमोरियल स्कूल के पास सुपेला भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-490023 से प्रकाशित। संपादक : संजय तिवारी, मो. 9200000214 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारा न्यायलीन क्षेत्र दुर्ग होगा। Email : loktantraprahrinews@gmail.com